सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh
RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number : F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 02, अंक 300, नई दिल्ली । बुधवार, 08 जनवरी 2025, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

अच्छे और सच्चे रिश्ते न तो खरीदे जा सकते हैं, न ही उधार लिए जा सकते हैं, इसलिए उन लोगों को जरूर महत्व दें, जो आपको महत्व देते हैं।

03 दिल्ली के बुजुर्गों को मिला संजीवनी योजना का कवच
06 हीटिंग उपकरणों का स्वास्थ्य पर कितना असर
08 चुनाव आयोग ने दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान किया

नई दिल्ली स्टेशन पहुंचे रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव, टैक्सी ऑटो वालों को दी गुड न्यूज

संजय बाटला

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली सहित दिल्ली के अन्य बड़े रेलवे स्टेशनों पर कैब और ऑटो पार्किंग शुल्क में कमी की घोषणा की है। कैब चालकों को अब 1200 रुपये प्रति माह की जगह 400 रुपये और ऑटो चालकों को 700 रुपये की जगह 200 रुपये पार्किंग शुल्क देना होगा। कुलियों की समस्याओं का समाधान करने का भी आश्वासन दिया गया है।

नई दिल्ली। नई दिल्ली सहित दिल्ली के अन्य बड़े स्टेशनों पर कैब और आटो पार्किंग के शुल्क में कमी कर दी गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशनों पर आटो व कैब चालकों और कुलियों से मुलाकात करने के बाद इसकी घोषणा की। कैब चालक को अब 12 सौ रुपये प्रति माह की जगह चार सौ और ऑटो चालकों को सात सौ की जगह मात्र दो सौ रुपये पार्किंग देना होगा। कुलियों की समस्या भी हल करने का आश्वासन दिया।

मंत्री ने मौके पर ही पार्किंग शुल्क में कमी की घोषणा की

मंगलवार दोपहर वह प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के साथ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। कैब व आटो चालकों और कुलियों के प्रतिनिधियों ने उनसे मुलाकात कर मांग पत्र सौंपा। मंत्री ने मौके पर ही पार्किंग शुल्क में कमी की घोषणा कर दी।

कुलियों ने प्रत्येक स्टेशन पर आराम घर बनाने, परिवार को 20 लाख रुपये तक की बीमा व उपचार की सुविधा देने, बच्चों की पढ़ाई की सुविधा देने और वर्दी की समस्या हल करने की मांग की। रेल मंत्री ने कहा, 50 से अधिक कुली जिस स्टेशन पर होंगे उन्हें आराम घर मिलेगा।

कुलियों की समस्याओं का समाधान करने का भी दिया आश्वासन

आयुष्मान योजना के अंतर्गत उनका व उनके स्वजनों का उपचार, रेलवे स्कूल में बच्चों को पढ़ाई की सुविधा मिलेगी। वर्दी की समस्या हल होगी। उन्होंने कुलियों को यात्रियों से अच्छे व्यवहार की सलाह दी। कहा, ऐसा कोई काम नहीं होने चाहिए जिससे कि उन्हें व रेलवे को लेकर यात्रियों के मन में गलत धारना बने। इस मौके पर ऑटो रिक्शा संघ के महामंत्री राजेंद्र सोनी सहित अन्य लोग उपस्थित थे।

टेंपल्स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत)
TOLWA
website : www.tolwa.in
Email : tolwadelhi@gmail.com
bathlasanjaybathla@gmail.com
रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम -डीएल -0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण
रजिस्टर्ड कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए -4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063
कॉरपोरेट कार्यालय :- 529, समयपुर, मेंन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ़ बड़ौदा दिल्ली 110042

महाराष्ट्र ने राज्य राजमार्गों पर सभी वाहनों के लिए फास्टैग किया अनिवार्य

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। देशभर में नेशनल हाईवे (राष्ट्रीय राजमार्गों) के बाद, महाराष्ट्र स्टेट हाईवे (राज्य राजमार्गों) का इस्तेमाल करने वाले सभी वाहनों के लिए फास्टैग के जरिए टोल भुगतान अनिवार्य करेगा। महाराष्ट्र कैबिनेट ने मंगलवार, 7 जनवरी अपने निर्णय का एलान किया कि सभी वाहनों के लिए फास्टैग का अनिवार्य उपयोग 1 अप्रैल से लागू किया जाएगा। परिवहन विभाग द्वारा स्टेट हाईवे पर टोल प्रणाली में बदलाव का प्रस्ताव दिए जाने के बाद यह निर्णय लिया गया।

अक्तूबर 2024 का फैसला होगा रद्द!

राज्य राजमार्गों पर निजी कारों सहित सभी वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य करने के निर्णय का यह भी मतलब है कि मुंबई में पांच प्रवेश बिंदुओं पर कारों और एसयूवी के लिए टोल शुल्क माफ करने का राज्य सरकार का पिछला निर्णय भी इस साल 1 अप्रैल को समाप्त हो जाएगा। पिछले साल अक्तूबर में, सरकार ने दहिसर, एलबीएस रोड-मुलुंड, ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे-मुलुंड, ऐरोली क्रीक ब्रिज और वाशी प्रवेश बिंदुओं पर निजी वाहनों को टोल का भुगतान करने से छूट देने का फैसला किया था।

महाराष्ट्र में नए FASTag नियम: जानने योग्य मुख्य बातें

वर्तमान में, महाराष्ट्र में 22 राज्य राजमार्ग हैं जिन्हें लोक निर्माण विभाग और राज्य सड़क विकास निगम द्वारा विकसित किया गया है। इन 22 राजमार्गों पर सभी टोल प्लाजा राज्य सरकार द्वारा शासित हैं। महाराष्ट्र के परिवहन विभाग के एक अधिकारी ने कहा, "2021 से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा शासित राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए फास्टैग नीति लागू है। अब यह निजी खिलाड़ियों द्वारा संचालित राज्य राजमार्गों और उन पर टोल प्लाजा पर अनिवार्य होगा।₹

राज्य राजमार्गों पर फास्टैग टोल संग्रह प्रणाली को अनिवार्य बनाने का मकसद सरकार को टोल प्लाजा पर ट्रैफिक जाम को कम करने के साथ-साथ भुगतान प्रक्रिया को कैशलेस और पारदर्शी बनाने में मदद करना है। परिवहन विभाग के अधिकारी ने कहा कि फास्टैग से संबंधित सभी नियम राज्य राजमार्गों पर भी लागू रहेंगे। अधिकारी ने कहा, "फास्टैग नहीं लगाने वाले मोटर चालकों को नकद जैसे अन्य माध्यमों से भुगतान करने पर दोगुना टोल देना होगा।"

फास्टैग आरएफआईडी-आधारित इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली है। जिसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा 15 फरवरी, 2021 से पूरे भारत में शुरू किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल प्लाजा पर लगाए गए कैमरे टोल शुल्क काटने के लिए वाहन की विंडशील्ड पर लगे आरएफआईडी टैग को स्कैन करते हैं।

ब्लू लाइन पर मेट्रो की फ्रीक्वेंसी हुई खराब 8 से 10 मिनट के अंतराल पर मिल रही ट्रेन

संजय बाटला

दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन पर ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी कम होने से यात्रियों को परेशानी हो रही है। वैशाली से आनंद विहार होते हुए द्वारका सेक्टर 21 तक जाने के लिए सुबह-शाम व्यस्त समय में साढ़े पांच मिनट की फ्रीक्वेंसी है। गैर-व्यस्त समय में फ्रीक्वेंसी सात मिनट होने का दावा किया जाता है लेकिन वास्तविकता इससे अलग है। यात्रियों को अक्सर 8-10 मिनट तक इंतजार करना पड़ता है।

नई दिल्ली। एनसीआर में परिवहन सुविधा को गति देने के लिए दिल्ली मेट्रो के बाद नमो भारत ट्रेन का परिचालन तो शुरू हो गया, इससे मेरठ से दिल्ली के बीच सफर आसान भी हुआ है, लेकिन ब्लू लाइन पर ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी कम होना यात्रियों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है।

फ्रीक्वेंसी कम होने से परेशान हो रहे यात्री

इस वजह से यात्रियों के सफर के दौरान 20 से 25 मिनट समय सिर्फ ट्रेनों के इंतजार में लग रहा है। ब्लू लाइन पर वैशाली से आनंद विहार होते हुए द्वारका सेक्टर 21 की तरह जाने के लिए सुबह शाम व्यस्त समय में साढ़े पांच मिनट की फ्रीक्वेंसी है।

फ्रीक्वेंसी पर क्या है डीएमआरसी का दावा?

वहीं, गैर व्यस्त समय में फ्रीक्वेंसी सात मिनट होने का दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) द्वारा दावा किया जाता है। जबकि मंगलवार करीब 12 बजे आनंद विहार मेट्रो स्टेशन पर द्वारका सेक्टर 21 के लिए आठ मिनट बाद मेट्रो उपलब्ध होने की सूचना प्रदर्शित हो रही थी।

नमो भारत के लिए करना पड़ता है 15 मिनट का इंतजार

ऐसे में यदि कोई यात्री नमो भारत ट्रेन से मेरठ और गाजियाबाद से ट्रेन पकड़ कर आनंद विहार आता है तो पहले नमो भारत ट्रेन के लिए स्टेशन पर 15 मिनट का इंतजार और फिर यदि आनंद विहार से मेट्रो पकड़कर दिल्ली में कहीं जाना हो तो मेट्रो के लिए आठ से दस मिनट के इंतजार को मिलाकर करीब 25 मिनट का समय ट्रेनों के इंतजार में निकल रहा है। फेज तीन में ब्लू लाइन का विस्तार होने से पहले मेट्रो कम समय के अंतराल पर उपलब्ध होती थी। फेज तीन में ब्लू लाइन का विस्तार होने के बाद फ्रीक्वेंसी प्रभावित हुई है।

मैजेंटा लाइन पर जनकपुरी पश्चिम-कृष्णा पार्क सेक्शन शुरू

दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) ने रविवार को मैजेंटा लाइन पर जनकपुरी पश्चिम और कृष्णा पार्क एक्सटेंशन के बीच 2.8 किलोमीटर लंबे हिस्से पर यात्री सेवाएं शुरू कर दी।

यह मेट्रो नेटवर्क विस्तार के चौथे चरण का पहला परिचालन खंड है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए खंड का उद्घाटन किया और 26.5 किलोमीटर लंबे रिठाला-नरेला-कुंडली मेट्रो कॉरिडोर के निर्माण की आधारशिला रखी, जो सोनीपत तक विस्तारित होगा।

दिल्ली में अब मजदूर और कैब ड्राइवरों का भी होगा घर

25 फीसदी तक छूट; डीडीए ने लॉन्च की ये तीन नई आवासीय स्कीम

परिवहन विशेष न्यूज

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने नए साल के अवसर पर तीन नई आवासीय योजनाएं शुरू की हैं। इनमें श्रमिक आवास योजना 2025 सबका घर आवास योजना 2025 और स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2025 शामिल हैं। इन योजनाओं के तहत निर्माण श्रमिकों ऑटो रिक्शा और कैब ड्राइवरों स्ट्रीट वेंडरों शहीदों की पत्नियों दिव्यांगों एससी/एसटी आदि को 25 प्रतिशत की विशेष छूट दी जाएगी।

नई दिल्ली। दिल्ली विकास प्राधिकरण डीडीए ने नए साल के अवसर पर मंगलवार को तीन नई आवासीय योजनाएं लांच की। इनमें श्रमिक आवास योजना 2025, सबका घर आवास योजना 2025 और स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2025 शामिल हैं।

डीडीए श्रमिक आवास योजना 2025

यह योजना मुख्य रूप से भवन और निर्माण श्रमिक के लिए है। इसके लिए जरूरी है कि श्रमिकों का पंजीकरण दिल्ली बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड (डीबीओसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी) के साथ होना चाहिए। इस योजना में नरेला में 700 ईडब्ल्यूएस फ्लैट तैयार किए गए हैं।

यह स्कीम पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर है। इसमें 25 प्रतिशत छूट के साथ फ्लैट दिए जाएंगे। इनकी शुरुआती कीमत 8.65 लाख रुपये है। 50 हजार रुपये से बुकिंग करा सकते हैं। बुकिंग 15 जनवरी से शुरू होगी और 31 मार्च को खत्म होगी।

डीडीए सबका घर आवास योजना 2025

इस योजना में कुछ खास कैटेगरी के लोगों को फ्लैट दिए जाएंगे। इनमें आटो रिक्शा ड्राइवर और कैब ड्राइवर (दिल्ली में पंजीकृत), पीएम स्वनिधि योजना में स्ट्रीट वेंडर या हाकर के रूप में पंजीकृत, शहीदों की पत्नी, दिव्यांग, एससी/एसटी आदि शामिल हैं।

इस योजना में ईडब्ल्यूएस और एलआइजी फ्लैट लोकनायक पुरम, सिरसपुर और नरेला में हैं। वहीं एमआइजी व एचआइजी फ्लैट लोकनायक पुरम तथा नरेला में हैं। इसमें भी 25 प्रतिशत की विशेष छूट दी जाएगी। इनकी भी शुरुआती कीमत 8.65 लाख रुपये है। पंजीकरण 15 जनवरी से शुरू होंगे।

डीडीए स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2025

इस योजना में फ्लैट की बिक्री ई-नीलामी के जरिए होगी। इसके तहत 110 एचआइजी, एमआइजी और एलआइजी फ्लैट की बिक्री की जाएगी। इन फ्लैटों का शुरुआती मूल्य 29 लाख रुपये है। इस योजना में पंजीकरण 14 जनवरी को सुबह 11 बजे से शुरू होगा। फार्म जमा कराने की आखिरी तारीख छह फरवरी है। आनलाइन नीलामी 11 फरवरी को होगी।

अधिकारियों का कहना है कि इन योजनाओं के बारे में अधिक जानकारी डीडीए की वेबसाइट eservices.dda.org.in से ली जा सकती है। साथ ही डीडीए के हेल्पलाइन नंबर 1800110332 पर काल करके भी इन योजनाओं के बारे में और अधिक जाना जा सकता है।

30 दिसंबर को ही बोर्ड बैठक में हुआ था निर्णय

डीडीए की आवासीय योजनाओं में अब निर्माण श्रमिकों, दिव्यांगों, आटो-कैब चालकों को 25 प्रतिशत की छूट देने का निर्णय 30 दिसंबर को ही डीडीए के अध्यक्ष व एलजी वीके सक्सेना की अध्यक्षता में हुई बोर्ड बैठक में लिया गया था।

बोर्ड बैठक में प्राधिकरण की तीन आवासीय योजनाओं को शुरू करने की भी मंजूरी मिली थी। ये योजनाएं नरेला, सिरसपुर और लोकनायकपुरम में है।

इन योजनाओं में पीएम-विश्वकर्मा के लाभार्थियों सहित महिलाओं और एससी/एसटी वर्ग के व्यक्ति, शहीद सैनिकों की विधवाओं, पूर्व सैनिक और पीएम-एसवीएनिधि योजना सहित वीरता पुरस्कार विजेताओं को भी 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

दिल्ली रूट पर इलेक्ट्रिक बसों के लिए बनेंगे चार्जिंग स्टेशन, जमीन की चिह्नित

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। सरकार प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से दिल्ली के लिए परिवहन सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए 30 इलेक्ट्रिक सुपर लग्जरी बसों की खरीद करने जा रही है। इसको देखते हुए एचआरटीसी ने इन बसों को बीच रास्ते में चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके तहत हरियाणा और दिल्ली में चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए पर्यटन और रोडवेज की जमीन चिह्नित की जा रही है। इसके लिए एक टीम का गठन भी किया गया है। यह टीम जगह-जगह जाकर जमीन तलाशने का काम कर रही है। एचआरटीसी शिमला, धर्मशाला, मनाली और रिवाल्सर समेत कई क्षेत्रों से दिल्ली के लिए बस सुविधा उपलब्ध करवाती है। इन रूट पर लोगों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए सुपर लग्जरी बसें खरीद की प्रक्रिया चल रही है। एक बार चार्जिंग करने पर यह बसें करीब 200 किलोमीटर का सफर तय करती है लेकिन इन रूटों की दूसरी इससे अधिक है। इस वजह से बसों को बीच रास्ते में चार्ज करने की जरूरत पड़ेगी। इसको देखते हुए एचआरटीसी बसों की खरीद से पहले ही इन चार्जिंग स्टेशन को तैयार करने में जुट गया है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के कारण सरकार ने इलेक्ट्रिक, सीएनजी और बीएस-6 बसों के प्रवेश को ही मान्य किया है। इस वजह से एचआरटीसी की दिल्ली के लिए चलने वाली 29 में से 13 वोल्वो बसें बंद हो गई थी। इसको देखते हुए सरकार अब आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर लग्जरी इलेक्ट्रिक बसों की खरीद करने जा रहा है। एचआरटीसी के मुताबिक आधुनिक चार्जर की मदद से अब महज 40 मिनट में बस की बैटरी को चार्ज किया जा सकता है। इन्ही आधुनिक चार्जर को इन स्टेशनों पर स्थापित किया जाएगा। ऐसे में जब इन बसों को चार्जिंग के लिए जब रोका जाएगा तो इस दौरान सवारियां नजदीकी ढाबों और होटल में खाना खा सकेंगी। इससे सफर में बैटरी चार्जिंग के लिए अतिरिक्त समय भी नहीं लगेगा। निगम हरियाणा और दिल्ली में इन स्टेशनों को स्थापित करने के लिए जमीन लीज पर लेने की योजना बना रहा है। निगम के मुताबिक सरकार की खरीद प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही स्टेशन को भी स्थापित कर दिया जाएगा। इससे खरीद के साथ ही इन रूटों पर लोगों को आधुनिक बसों की सुविधा मिल सकेगी।

सर्दियों में मुश्किल हो रहा है दही जमाना, तो इस आसान ट्रिक से घर पर तैयार करें फ्रेश कर्ड

दही पोषक तत्वों से भरपूर एक सुपरफूड है जिसे कई लोग खाना पसंद करते हैं। सेहत को फायदा पहुंचाने के साथ ही यह बालों और त्वचा को भी फायदा पहुंचाता है। हालांकि बाजार में मिलने वाला दही कई बार फ्रेश नहीं होता है। ऐसे में आप खुद घर ही ताजा दही जमा सकते हैं। सर्दियों में दही जमाने के लिए ये ट्रिक आपके काम आएगी।

नई दिल्ली। दही एक बेहद जरूरी और फायदेमंद पौष्टिक आहार है, जो एक बेहतरीन प्रो–बायोटिक है। ये गट हेल्थ के लिए प्रो–बायोटिक का पावरहाउस मानी जाती है। दही से पाचन क्षमता बढ़ती है और इसमें मौजूद कैल्शियम हड्डियां मजबूत करता है। दही में प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, लैक्टिक एसिड जैसे पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जो इसे एक परफेक्ट सुपरफूड बनाते हैं।

दही के फायदे

यह बाल और स्किन के लिए भी बेहद फायदेमंद है। इसलिए यह सेहत के साथ-साथ त्वचा और बालों के लिए भी गुणकारी माना जाता है। इसे एक फेस क्लींजर की तरह या फिर फेस पैक में इस्तेमाल किया जाता है। सन टैन हटाने ने भी दही बहुत ही काम आती है। मुल्तानी मिट्टी के साथ फेस पैक लगाने पर ये एक मॉश्चराइजर का काम करती है। बालों से डैंड्रफ हटाने के लिए भी दही के हेयर मास्क का इस्तेमाल किया जाता है।

हालांकि, बाजार में मिलने वाला दही कई बार उतना फ्रेश नहीं होता है। ऐसे में आप घर पर ही इसे तैयार कर सकते हैं। अगर आप भी दही खाने के शौकीन हैं, लेकिन सर्दियों में आपको दही जमाने में दिक्कत होती है, तो चलिए आज जानते हैं ऐसी ट्रिक जिसे आजमाने से सर्दियों में दही जमाने का काम आसान हो जाएगा। चलिए जानते हैं कि सर्दियों में कैसे जमाएं दही-

सर्दियों में ऐसे जमाएं दही-

दूध को गैस पर उबालें और गुनगुना होने तक ठंडा होने दें।

मल्टी कुक माइक्रोवेव सेफ तवा लें।

इसे माइक्रोवेव में 10 मिनट के लिए कन्वेक्शन मोड पर 200 डिग्री तापमान पर प्रिहीट कर लें।

गुनगुने दूध में दो चम्मच दही डाल कर मिक्स करें।

माइक्रोवेव प्रिहीट हो जाए तो इस गर्म तवे के ऊपर दही मिक्स दूध के कटोरे को रखें।

कटोरे को अच्छे से ढंक दें और माइक्रोवेव को बंद कर दें।

दो घंटे के लिए इसी तरह जमने के लिए छोड़ दें।

इस दौरान माइक्रोवेव को बार बार खोल कर चेक न करें।

दो से तीन घंटे बाद माइक्रोवेव से कटोरे को निकालें।

फ्रेश दही जम कर तैयार है।

इसी तरह सर्दियों में दही जमाने का एक दूसरा तरीका भी बहुत प्रचलित है, जिसे आप नीचे दिए तरीके से फॉलो कर सकते हैं-

गुनगुने दूध में दो चम्मच दही डालें और मिक्स करें।

ऊपर से दो लाल खड़ी मिर्च या हरी मिर्च रखें और अच्छे से ढंक कर 6 से 7 घंटे के लिए छोड़ दें।

दही जम कर तैयार मिलेगी।

संस्कृति और परंपरा का अनूठा संयोजन है क्रिश्चियन आइकनोग्राफी, मूर्तिकला के शौकानों के लिए है परफेक्ट

गोवा की अपनी परंपराओं और आधुनिक भारतीय कला के तत्वों का अद्भुत संयोजन है क्रिश्चियन आइकनोग्राफी। इसके तहत भारतीय कलात्मक शैलियों और यूरोपीय रूपांकनों के संयोजन से बने ईसाई प्रतीकों के ऐसे अनूठे शिल्प जो दक्षिण एशिया की विशिष्ट सांस्कृतिक धरोहर हैं। यह औपनिवेशिक गोवा में भारत- पुर्तगाली कला की समृद्धता और वैश्विक व्यापकता को बड़ी खूबसूरती से दर्शाती है।

नई दिल्ली। बंद आंखें, हल्का-सा नीचे की ओर झुका हुआ सिर और प्रार्थना के भाव में जुड़े हुए हाथ, राजा रवि वर्मा द्वारा चित्रित कैलेंडर छवियों की तरह दिखने वाली इस साड़ी पहने महिला की प्रतिमा पवित्र किताब से जुड़े अर्धचंद्र के ऊपर खड़ी है।

इसे देख कर समझ आता है कि क्रिश्चियन आइकनोग्राफी गोवा की अपनी परंपराओं और आधुनिक भारतीय कला के तत्वों का कितना अद्भुत संयोजन है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में हाथीदांत से निर्मित वर्जिन मेरी की यह मूर्ति औपनिवेशिक गोवा में भारत- पुर्तगाली कला की समृद्धता और वैश्विक व्यापकता को बड़ी खूबसूरती से दर्शाती है।

कई कलाओं से प्रेरणा

16वीं शताब्दी की शुरुआत में पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा करने के बाद ईसाई मिशनरी गोवावासियों के बीच ईसाई धर्म का प्रचार-प्रसार करने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे। उन्होंने बड़ी संख्या में जगह-जगह चर्च का निर्माण कराया और स्थानीय कारीगरों को लकड़ी और हाथीदांत की मदद से बने, दीवार पर लटकाए जा सकने वाले बड़े चित्रों से लेकर पोर्टेबल आइकन तक कैथोलिक छवियों को तैयार करने का निर्देश दिए। इनमें ईसा मसीह के सूली पर चढ़ाए जाने, वर्जिन मेरी एवं मैडोना आदि विविध छवियां शामिल थीं।

ऐसी कलाकृतियों के निर्माण में जेसुइट्स ने विशेष रूप से सहयोगात्मक भावना अपनाई। वे सचित्र संदर्भ के रूप में यूरोप से प्रतीकात्मक छवियों के प्रिंट लाए, लेकिन उन्होंने भारतीयता के दृष्टिगत स्वदेशी कारीगरों को शैलीगत बदलावों की पूर्ण अनुमति दी। नतीजतन, स्थानीय कारीगरों ने सांस्कृतिक कला के क्षेत्र में पहले से उपस्थित हिंदू, बौद्ध और जैन धार्मिक छवियों से प्रेरणा लेते हुए उपमहाद्वीप की विशिष्ट मूर्तिकला शैलियों में यीशु, मदर मेरी और विभिन्न संतों जैसी सामान्य ईसाई आकृतियों की फिर से कल्पना की व उनका निर्माण-कार्य किया।

क्या है स्वीप डायवोर्स? कपल्स के बीच क्यों बढ़ रहा है इसका ट्रेंड, पढ़ लीजिए फायदे और नुकसान

आजकल रिश्तों में एक नया ट्रेंड तेजी से फेमस हो रहा है जिसे स्लीप डिवोर्स (Sleep Divorce) कहा जाता है। यह शब्द अब कपल्स के बीच आम बातचीत का हिस्सा बन गया है लेकिन अगर आप अबतक इससे अनजान हैं तो इस आर्टिकल में हम इसकी पूरी डिटेल लेकर आए हैं जिससे आप समझ पाएंगे कि रिलेशनशिप (Sleep Divorce In Relationship) में इसके क्या फायदे और नुकसान हो सकते हैं।

नई दिल्ली। आजकल के समय में, जब काम की भागदौड़ ने हमारी लाइफ को पूरी तरह से घेर रखा है, तब रिश्तों में भी कई बदलाव देखने को मिल रहे हैं। इन बदलावों में से एक है 'नींद का तलाक' या 'स्लीप डिवोर्स'।

स्लीप डिवोर्स एक ऐसा चलन है जिसमें कपल्स एक ही घर में रहते हुए अलग-अलग बिस्तर या कमरों में सोते हैं। यह एक तरह का समझौता है, जिसमें दोनों पार्टनर अपनी नींद को तवज्जो देते हैं। ध्यान रहे, इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि उनके रिश्ते में कोई समस्या है। जी हां, आइए इस आर्टिकल में विस्तार से जानते हैं रिलेशनशिप में इसके फायदे और नुकसान (Benefits and Harms of Sleep Divorce) के बारे में।

क्या होता है स्लीप डिवोर्स?

लंबे समय से यह परंपरा रही है कि शादी के बाद कपल एक ही बिस्तर पर सोते हैं, लेकिन हाल के समय में 'स्लीप डिवोर्स' का चलन तेजी से बढ़ रहा है, जहां कपल अलग-अलग कमरों या बिस्तरों पर सोते हैं। हालांकि वे शारीरिक रूप से अलग हो जाते हैं, लेकिन इमोशनल कनेक्शन बना रहता है। इसका खास मकसद अच्छी नींद लेना और रिश्ते में ताजगी को बनाए रखना है।

क्यों बढ़ रहा है स्लीप डिवोर्स का ट्रेंड?

बेहतर नींद

कई बार, एक पार्टनर की नींद की आदतें दूसरे पार्टनर को परेशान कर सकती हैं। जैसे, एक पार्टनर को रात में बहुत ज्यादा हिलना-डुलना पसंद हो सकता है, जबकि दूसरे पार्टनर को शांत माहौल में सोना पसंद हो। ऐसे में, अलग-अलग सोकर दोनों ही पार्टनर अच्छी नींद ले सकते हैं।

स्ट्रेस कम करना

आजकल स्ट्रेलफुल लाइफ में, नींद की कमी एक बड़ी समस्या बन गई है। अलग-अलग सोकर, कपल्स तनाव को कम कर सकते हैं और अपने मेंटल हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं।

पर्सनल स्पेस

हर इंसान को थोड़ा-सा पर्सनल स्पेस चाहिए होता है। अलग-अलग सोकर, कपल्स को अपना पर्सनल स्पेस मिल जाती है, जिससे वे खुद को रिचार्ज कर सकते हैं।

शारीरिक समस्याएं

कई बार शारीरिक समस्याएं जैसे कि स्लीप एपनिया, एक पार्टनर की नींद को बाधित कर सकती हैं। ऐसे में, अलग-अलग सोकर दोनों पार्टनर को बेहतर नींद मिल सकती है।

स्लीप डिवोर्स के फायदे

अच्छी नींदः यह सबसे बड़ा फायदा है। अच्छी नींद से फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों ही बेहतर होते हैं।

तनाव में कमीः अच्छी नींद से तनाव कम होता है और मूड बेहतर होता है।

रिश्ते में सुधारः अक्सर, नींद की कमी के कारण कपल्स के बीच झगड़े होते हैं। अलग-अलग सोकर, इन झगड़ों को कम किया जा सकता है और रिश्ते में सुधार हो सकता है।

प्रोडक्टिविटी में इजाफाः अच्छी नींद से प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी होती है।

स्लीप डिवोर्स के नुकसान

इमोशनल डिस्टेंसः कुछ लोगों का मानना है कि अलग-अलग सोने से कपल्स के बीच भावनात्मक दूरी बढ़ सकती है।

रोमांटिक रिश्तों पर असरः कुछ कपल्स के लिए, एक साथ सोना रोमांटिक रिलेशनशिप का एक अहम हिस्सा होता है। अलग-अलग सोने से इस पर असर पड़ सकता है।

सोशल प्रेशरः समाज में अभी भी यह मान्यता है कि कपल्स को एक साथ सोना चाहिए। इसलिए, स्लीप डिवोर्स को लेकर कुछ लोग शर्मिंदगी महसूस कर सकते हैं।

स्लीप डिवोर्स एक ऐसा चलन है जो कपल्स के लिए एक ऑप्शन हो सकता है। हालांकि, यह हर कपल के लिए सही नहीं हो सकता। अगर आप और आपका पार्टनर नींद की समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो आप स्लीप डिवोर्स के बारे में विचार कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले कि आप कोई फैसला लें, दोनों को मिलकर बात करनी चाहिए और यह समझना चाहिए कि आपके लिए क्या सबसे अच्छा है।

राष्ट्रीय शीतकालीन त्वचा राहत दिवस

सर्दी के मौसम में तेजी से वृद्धि के साथ, 8 जनवरी को राष्ट्रीय शीतकालीन त्वचा राहत दिवस हमें उन सभी तरीकों की याद दिलाता है जिनसे हम अपनी त्वचा को सबसे कठोर तत्वों से भी मुरझाने से बचा सकते हैं। बाहर गिरता तापमान और अंदर बढ़ता तापमान हवा में नमी की मात्रा को कम कर देता है। सबसे पहले हमारी त्वचा को इसका एहसास होता है।

सर्दियों में त्वचा की देखभाल के टिप्स जब ठंड शुरू हो जाए, तो लंबे समय तक गर्म पानी से नहाने के प्रलोभन से बचें। गर्मी त्वचा से प्राकृतिक तेल (जिसे सेरामाइड्स कहा जाता है) को हटा देती है और सूजन पैदा करती है। त्वचा की कोशिकाएँ सूज जाती हैं और जब वे सूख जाती हैं तो वे खराब तरीके से ग्राउट की गई टाइलों की तरह ढीली हो जाती हैं और फट जाती हैं। इसके बजाय, कम समय के लिए गुनगुने पानी से नहाएँ और सौम्य क्लींजर का इस्तेमाल करें। सर्फेक्टेंट और पीएच संतुलन के दावों वाले कठोर साबुन त्वचा के लिए कठोर हो सकते हैं। और रगड़ें नहीं! कोमल रहें और पानी और झाग को अपना काम करने दें। नहाने के बाद, त्वचा को मुलायम तौलिये से थपथपाकर सुखाएँ। रगड़ने से जलन और सूजन बढ़ जाती है। नमी को अंदर रखने के लिए दरवाज़ा बंद करके मॉइस्चराइज़र लगाएँ। कपड़े पहनते समय, परतों में कपड़े पहनें। सबसे करीबी परत प्राकृतिक रेशों से बनी होनी चाहिए। सिंथेटिक सामग्रियों की तुलना में फलालैन और सूती जैसे मुलायम कपड़े बहुत कम या बिलकुल भी जलन पैदा नहीं करते हैं। परतें ठंड के मौसम में भी ज़्यादा प्रभावी होती हैं।

सर्दियों में त्वचा को राहत देने वाला दिन कैसे मनाएं? सर्दी में अपनी त्वचा की सुरक्षा और नमी बनाए रखकर उसकी देखभाल करें।

राष्ट्रीय शीतकालीन त्वचा राहत दिवस का इतिहास सेरावी स्किनकेयर के निर्माताओं ने सर्दियों में त्वचा को मिलने वाली अतिरिक्त देखभाल के प्रति जागरूकता लाने के लिए राष्ट्रीय शीतकालीन त्वचा राहत दिवस की स्थापना की।

एसिडिटी से तंग है तो अपनाएं ये 4 घरेलू नुस्खे

आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम खुद को अच्छे से वक़्त देना भूल चुके हैं. इस बदलते लाइफस्टाइल का सबसे अधिक प्रभाव हमारी सेहत पर पड़ता है. लोग अपने काम-काज में इतने व्यस्त हो चुके हैं कि सही डाइट नहीं ले पाते और फिर बीमार पड़ जाते हैं. इन्ही गंभीर बिमारियों से एक बीमारी है एसिडिटी. वैसे देखा जाए तो एसिडिटी कोई बीमारी नहीं है. असल में यह हमारी बदलती हुई जीवनशैली के कारण हमे आ घेरती है.

एसिडिटी के दौरान खट्टी डकार आना, पेट फूलना, सीने में जलन होना आदि लक्ष्ण दिखाई देते हैं. एसिडिटी के अनेकों कारण हो सकते हैं. ख़ास कर जो लोग तले भुने खाने खाते हैं, उन लोगों में एसिडिटी होना आम बात है. आज हम आपको एसिडिटी के कुछ ऐसे उपचार बताने जा रहे हैं, जिन्हें अपना कर आप चुटकियों में एसिडिटी से छुटकारा पा सकते हैं.

एसिडिटी बनने की प्रक्रिया आप में से अधिकतर लोग एसिडिटी के पीछे का कारण खान-पान की आदतों को मानते होंगे. लेकिन ऐसा बिलकुल भी नहीं है. एसिडिटी का कारण खाली पेट भी हो सकता है. दरअसल, आज के समय में लोग डाइटिंग पर ख़ास ध्यान देते हैं. ऐसे में कईं बार भूख लगने पर भी लोग समय पर खाना नहीं खाते जिसके कारण उनके शरीर में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है. यही एसिड धीरे धीरे एसिडिटी एवं जलन का रूप ले लेता है. इसके इलावा धुम्रपान, अधिक मात्र में चाय-काफी का सेवन, शराब आदि एसिडिटी के प्रमुख कारण हैं.

तुलसी के पत्ते तुलसी के पत्ते देवी देवताओं का प्रतीक हैं. आयुर्वेद ग्रंथ में तुलसी को सबसे उत्तम आयुर्वेदिक औषधि बताया गया है. इसकी पत्तियों में सुखदायक, वायुनाशक और वात हरने वाले गुण होते हैं, जो कि सीने में होने वाली जलन, पेट की गैस आदि जैसी समस्याओं से तुरंत राहत देते हैं.

ऐसे करें इस्तेमाल यदि आपको पेट में गड़बड़ी महसूस होने लगे या फिर आपके सीने में जलन हो तो तुलसी की कुछ पत्तियों को तुरंत चबाकर खा लें. या फिरआप एक कप पानी में चार-पांच तुलसी की पत्तियों को डालकर उबालें और कुछ मिनट के लिए ठंडा होने दें. ठंडा होने के बाद इसमें शहद घोल कर पी लें आपको एसिडिटी से राहत मिलेगी.

लौंग का सेवन लौंग हर भारतीय रसोई घर में पाया जाने वाला एक उत्तम मसाला है. विशेषज्ञों के अनुसार लौंग एक पारंपरिक आयुर्वेदिक दवा है. यह खाने को स्वादिष्ट बनाने में काम आटा है. इसमें आपके स्वास्थ्य को दुरुस्त रखने के कई गुण शामिल होते हैं।

लौंग को आप नियमित रूप से अपने व्यंजनों में शामिल करें. इसके अलावा एसिडिटी से तुरंत राहत के लिए दो-तीन लौंग लें और खूब चबा-चबाकर खाएं. अगर आपको लौंग कड़वा लगे तो आप इसे इलायची के साथ चबा कर भी खा सकते हैं. एसिडिटी खत्म करने के साथ-साथ यह मुंह की दुर्गंध से भी छुटकारा दिलाती है.

दालचीनी एक ऐसा मसाला है, जो नेचुरल प्राकृतिक अम्लत्व नाशक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है. एसिडिटी को खत्म करने व पाचन-तंत्र को दुरुस्त रखने में दालचीनी को सबसे उत्तम आयुर्वेदिक औषधि माना गया है. ऐसे करें इस्तेमाल दालचीनी का इस्तेमाल करने के लिए आप एक कप पानी में आधा चम्मच दालचीनी मिला लें. अब इस पानी को कुछ मिनट तक उबाल लें और फिर इस दालचीनी की चाय का सेवन दिन में दो से तीन बार करें. इससे आपको एसिडिटी से छुटकारा मिलेगा.

जीरे का सेवन वैसे तो दाल-सब्जी में स्वाद बढाने के लिए मसले के रूप में जीरे का इस्तेमालकिया जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि छोटा-सा दिखने वाला यह जीरा असल में बहुत काम का होता है. पेट में जाकर यह एसिड न्यूट्रालाइजर की तरह काम करता है।

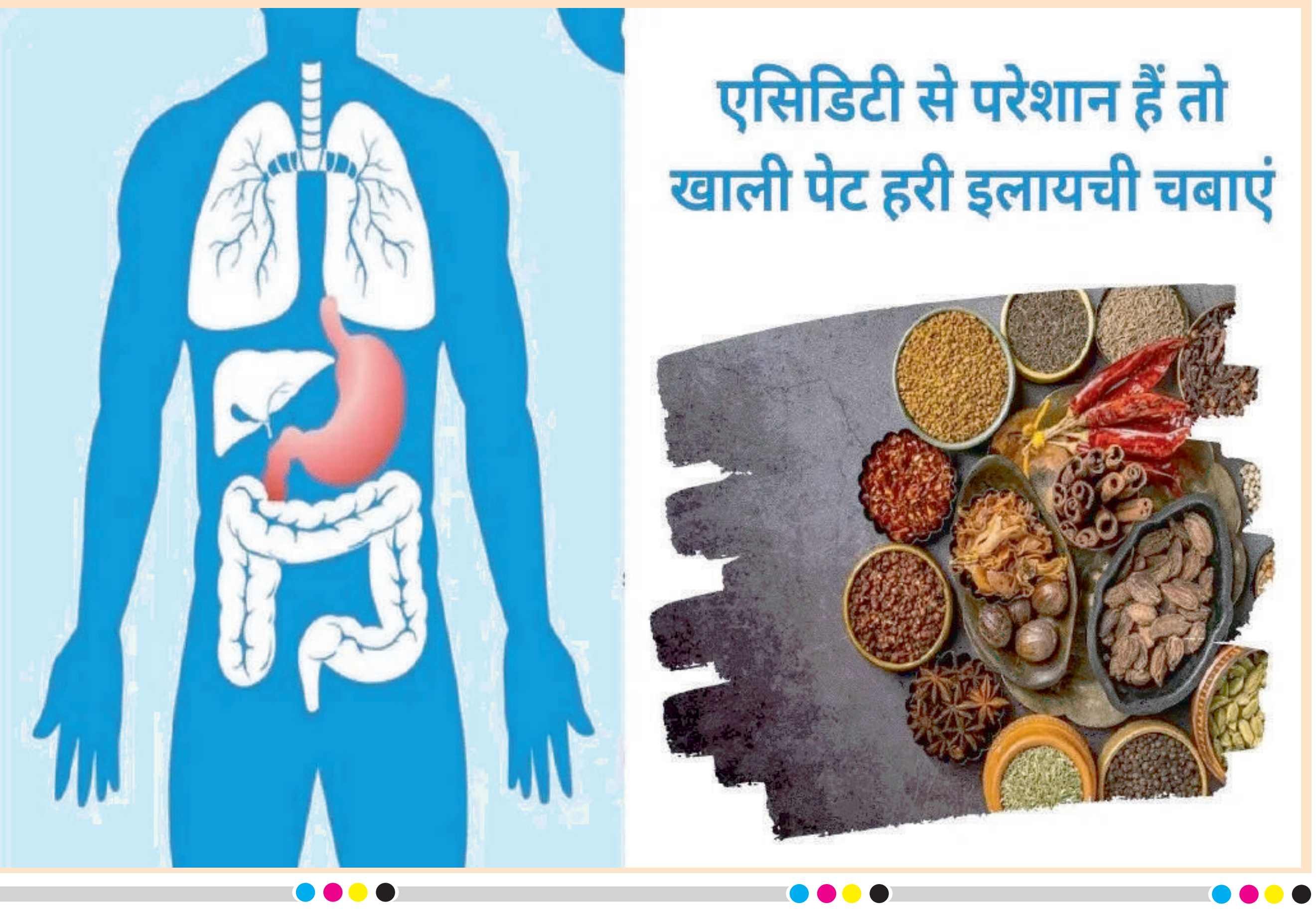

चुनाव आयोग ने दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान किया

सुषमा रानी

नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने मंगलवार को दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर 5 फरवरी 2025 को मतदान होगा। 8 फरवरी 2025 को मतगणना होगी ।मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि ईवीएम पर आरोप लगते रहते हैं. इस बार वोटर लिस्ट से नाम काटने की भी शिकायत की गई. वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोप लगे.

पिछले कुछ विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस पार्टी ने खुलकर ईवीएम पर सवाल उठाए हैं. वहीं, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में चुनाव से पहले वोटर लिस्ट से कई मतदाताओं के नाम काटने का आरोप लगाए हैं.

इन आरोपों पर राजीव कुमार ने कहा कि लिस्ट से वोटर का नाम हटाने पर पूरी प्रक्रिया का पालन किया जाता है. उन्होंने कहा कि अगर अचानक एक क्षेत्र से 10-20 हज़ार नाम काट दिए जाएंगे, तो ऐसे में बड़ा मामला होगा. उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों की सहमति से वोटर लिस्ट अपडेट होती है.

उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट लगातार अलग-अलग आदेशों में ये कहते आए हैं कि ईवीएम में किसी तरह की गड़बड़ी या हैकिंग नहीं हो सकती है.

अभी पिछले चुनाव में बड़ा हल्ला हो गया कि हमारा हेलीकॉप्टर चेक किया गया, दूसरे का नहीं किया गया. अधिकारियों को धमकाने तक की नौबत आई है. लेकिन हम रोक लेते हैं खुद को क्योंकि इससे सबके लिए एक सामान अवसर रुकते हैं. सीईसी ने सभी राजनीतिक दलों को चुनाव में शालीनता बनाए रखने की भी नसीहत दी. उन्होंने कहा कि इसी से हमारा लोकतंत्र आगे पनपेगा.

चुनाव में 85 वर्ष से अधिक आयु के तथा दिव्यांग मतदाताओं के लिए घर से मतदान की सुविधा रहेगी। मतदान में आसानी के लिए मतदान केंद्रों पर स्वयंसेवक, व्हीलचेयर तथा रैंप बनाए जाएंगे। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को नसीहत भी दी। चुनाव प्रचार में भाषा का ख्याल रखें। महिलाओं के खिलाफ गलत भाषा का इस्तेमाल न करें।

मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि 13 हजार से ज्यादा पोलिंग बूथ हैं। दिल्ली में कुल एक करोड़ 55,24,858 मतदाता हैं। इसमें

पुरुष मतदाता 85,49,645 हैं, जबकि 71,73,952 महिला मतदाता हैं। दिल्ली में दो लाख फर्स्ट वोटर हैं।

मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि मतदाता मतदान में हेराफेरी का हौवा है। शाम पांच बजे के बाद वीटीर में वृद्धि पर गलत बयानबाजी है। लोकसभा और महाराष्ट्र चुनाव में करोड़ों मतदाताओं के नाम गलत तरीके से जोड़े जाने के आरोप लगे। शक का इलाज किसी के पास नहीं है। वोटिंग पर झूठ के गुब्बारे न उड़ाएं। गड़बड़ी की शिकायत का हम जवाब देंगे। चुनाव को लेकर शंकाओं को खारिज करते हैं। चुनाव हम सबकी साझा विरासत है।

मुख्य चुनाव अधिकारी राजीव कुमार ने कहा कि EVM मतगणना के लिए पूर्णतया सुरक्षित हैं। EVM से छेड़छाड़ के आरोप निराधार हैं, हम अब इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि चुनाव के समय हम नहीं बोलते VVPAT प्रणाली वाली EVM मतदान प्रणाली की सटीकता सुनिश्चित करती है। पुराने पेपर बैलट की वापसी अनुचित और प्रतिगामी है। इसका उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया को पटरी से उतारना है ।राजधानी दिल्ली में मतदाता सूची पर छिड़े सियासी घमासान के बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने सोमवार को वोटरों की अंतिम सूची जारी कर दी। विधानसभा के आगामी चुनाव में 1,55,24,858 मतदाता मतदान पंजीकृत हैं। इसमें 2020 के मुकाबले करीब सात लाख से ज्यादा मतदाताओं की बढ़ोतरी हुई है।

पुरुष मतदाता ज्यादा : निर्वाचन आयोग के अुनसार, दिल्ली में इस बार 83.49 लाख पुरुष और 71.73 लाख महिला मतदाता हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान दिल्ली में 1,47,86,882 मतदाता थे। दिल्ली में 2.08 लाख मतदाता ऐसे हैं जो पहली बार मतदान करेंगे। मतदाता सूची जारी होने के बाद अब जल्द ही चुनाव की तारीख का ऐलान हो सकता है। माना जा रहा है कि फरवरी के पहले या दूसरे सप्ताह में चुनाव हो सकते हैं।

20 अगस्त से चला अभियान : निर्वाचन आयोग की ओर से बीते साल 20 अगस्त से मतदाता सूची के पुनरीक्षण के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया था। अक्टूबर 2024 में निर्वाचन आयोग ने ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की थी। इस सूची के मुताबिक, दिल्ली में 1,53,57,529 मतदाता थे। इस ड्राफ्ट मतदाता सूची को दिल्ली के सभी राजनीतिक दलों को निशुल्क उपलब्ध कराकर निर्वाचन आयोग ने लोगों से आपत्तियां और सुझाव मांगे।

दो लाख युवा पहली बार करेंगे मतदानः दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए तैयार की गई मतदाता सूची में 2.08 लाख मतदाता ऐसे हैं जो पहली बार मतदान करेंगे। वहीं, सात माह में राजधानी में 3.22 लाख मतदाताओं की संख्या बढ़ी है।

एक माह में तीन लाख से ज्यादा आवेदन आए

आयोग के मुताबिक, अक्टूबर से दिसंबर तक इस अभियान के दौरान 3,08,942 लोगों ने मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए आवेदन किए, वहीं 1,41,613 लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाने के लिए आवेदन प्राप्त हुए।

धोखाधड़ी में 24 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज

मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए लोगों की जबरदस्त भीड़ में फर्जीवाड़ा सामने आया है। इस दौरान लोगों ने फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत कर खुद को दिल्ली का निवासी बताया। आयोग ने 24 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है।

विकास के नाम पर दिल्ली को सिर्फ लूटने का काम किया : वीरेंद्र सचदेवा

सुषमा रानी

नई दिल्ली। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने मंगलवार को पत्रकार वार्ता में कहा कि आम आदमी पार्टी (आआपा) की सरकार ने दिल्ली में विकास के नाम पर भ्रष्टाचार कर दिल्ली को लूटने का काम किया।

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि न्यायालय की फटकार के बाद भी यह सरकार सीएजी रिपोर्ट को विधानसभा पटल पर नही रखी, जो यह स्थापित करता है कि सीएजी की रिपोर्ट से केजरीवाल डरते हैं।

उन्होंने कहा कि शीशमहल बंगले से जुड़ी सीएजी रिपोर्ट के हिस्से को कल मैंने दिल्ली वालों के समक्ष रखा, आज मैं दिल्ली सरकार के प्रचार विज्ञापन खेल पर सीएजी रिपोर्ट सामने रख रहा हूं, जो अरविंद केजरीवाल की पोल खोलने के लिए काफी है।

सचदेवा ने कहा कि आज हमने समाचार पत्रों के माध्यम से देखा कि शीशमहल बंगले पर सीएजी रिपोर्ट को सांसद संजय सिंह ने फर्जी रद्दी का कागज बताया है।

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा है कि संविधान के अनुसार भारत सरकार के सामान्य वित्त नियम कहते हैं कि किसी भी सरकार के खर्च तर्कसंगत होने चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के भी निर्देश हैं कि सरकारें विज्ञापन पर कुछ इस तरह खर्च करें कि विज्ञापन पर खर्च किसी भी सूरत मे योजना पर मूल खर्च से अधिक नहीं होना चाहिए।

उन्होंने वित्त वर्ष 2021-22 से जुड़ी सीएजी रिपोर्ट के हवाले से अरविंद केजरीवाल से जवाब मांगा कि कैसे उन्होंने अपनी चार योजनाओं के प्रचार पर मूल योजना खर्च से 31 गुणा खर्च कर डाला ?

सीएजी की रिपोर्ट बताती है कि 2021-22 वर्ष में सब कोविड से जूझ रहे थे उस वक्त केजरीवाल सरकार ने निम्न चार योजनाओं के नाम पर जनधन को स्व प्रचार पर लुटाया।

सचदेवा ने कहा कि केजरीवाल सरकार की जनधन बर्बादी पर चार सवाल जो सीएजी ने खड़े किये हैं, केजरीवाल आगे आयें और उन पर जवाब दें ? पहला बिजनेस ब्लास्टर स्कीम मूलधन खर्च 54.08 करोड़, प्रचार खर्च 80.02 करोड़ रुपये, दूसरा देश के मेंटोर मूल खर्च सिर्फ 1.90 करोड़, प्रचार खर्च 27.90 करोड़ रुपये, तीसरा पराली योजना सिर्फ 0.77 लाख, प्रचार खर्च 27.89 करोड़ रुपये और चौथा स्मॉग टावर मूल खर्च 20 करोड़, प्रचार खर्च 5.88 करोड़ रुपये किए गए।

तेजी से बढ़ रहा है ई-कचरा

आज पूरे विश्व में प्रौद्योगिकी हमारे दैनिक जीवन का एक अनिवार्य और महत्वपूर्ण हिस्सा हो गई है। हम काम से लेकर मनोरंजन और संचार से लेकर शिक्षा, व्यापार, चिकित्सा तक, लगभग-लगभग हर काम के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों का उपयोग करते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की तीव्र प्रगति के साथ, एक नई समस्या सामने आई है - ई-कचरा। आज दुनिया में ई-कचरा लगातार बढ़ रहा है क्यों कि एक तो तीव्र तकनीकी उन्नति हो रही है, दूसरा यह कि आज विभिन्न कंपनियां उपभोक्ताओं को इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के नए मॉडल में अपग्रेड करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए करती हैं, जिससे पुराने इलैक्ट्रोनिक सामान एक समय विशेष के बाद उपभोक्ताओं के लिए व्यर्थ हो जाते हैं। आज दुनिया में बहुत से लोग इस बात से अनजान हैं कि अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का सही तरीके से निपटान कैसे किया जाए, जिसके कारण वे इन उपकरणों को लैंडफिल में फेंक देते हैं और इस तरह से धरती पर ई-कचरा लगातार बढ़ रहा है। इसी संदर्भ में इन दिनों ग्लोबल ई-वेस्ट मॉनिटर 2024 की रिपोर्ट काफी चर्चा में है। हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (यूनिटार) ने इसे जारी किया है , जिसमें यह कहा गया है कि दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक कचरे का उत्पादन दर्ज ई-कचरे के पुनर्चक्रण की तुलना में पांच गुना तेजी से बढ़ रहा है। पाठकों को बताता चलूं कि यूएनआईटीएआर संयुक्त राष्ट्र की एक प्रशिक्षण शाखा है जो सरकारों, संगठनों और व्यक्तियों को वैश्विक चुनौतियों पर काबू पाने में मदद करती है। इसकी रिपोर्ट से यह पता चलता है कि वैश्विक ई-कचरा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है , जो 2010 में 34 बिलियन किलोग्राम से बढ़कर 2022 में 62 बिलियन किलोग्राम तक पहुंच गई। रिपोर्ट में यह बात कही गई है यदि यही प्रवृत्ति जारी रहती तो वर्ष 2030 तक यह लगभग 32 प्रतिशत बढ़कर 82 बिलियन किलोग्राम तक पहुंच जाएगी। वर्ष 2022 में जो रिकॉर्ड 62 मिलियन टन ई-कचरा उत्पन्न हुआ, वह वर्ष 2010 से 82% अधिक है। गौरतलब है कि इस 62 अरब किलोग्राम में से केवल 13.8 अरब किलोग्राम को ही 'औपचारिक रूप से एकत्रित और पर्यावरण की दृष्टि से उचित तरीके से पुनर्चक्रित' किया गया । यह भी उल्लेखनीय है कि 62 अरब किलोग्राम ई-कचरे में 31 अरब किलोग्राम धातु, 17 अरब किलोग्राम प्लास्टिक और 14 अरब किलोग्राम अन्य सामग्रियां (खनिज, कांच, मिश्रित सामग्री आदि) शामिल हैं। कहना ग़लत नहीं होगा कि ई-कचरा(इलैक्ट्रोनिक अपशिष्ट) सभी प्रकार के पुराने या त्याग दिए गए विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे टीवी, फ्रिज, वाशिंग मशीन व अन्य और ट्युबलाइट, बल्ब व सी.एफ.एल. जैसी अन्य चीजें, मोबाइल फोन, कम्प्यूटर, विभिन्न घरेलू उपकरण, कार्यालय सूचना और संचार उपकरण, प्लग या

बैटरी आदि होते हैं, जो मानव व जीवों के स्वास्थ्य, जैव-विविधता और पर्यावरण के लिए खतरनाक है, क्यों कि इनमें अनेक विषाक्त योजक या पारे, सीसा, कैडमियम तथा निकल जैसी धातुएं तथा अनेक खतरनाक पदार्थ शामिल होते हैं। सच तो यह है कि ई-कचरे के अनुचित प्रबंधन से पर्यावरण में पारा और ब्रोमीनयुक्त अग्निरोधी प्लास्टिक जैसे खतरनाक पदार्थ निकलते हैं , जिससे पर्यावरण, जैव-विविधता और मनुष्य और जीवों के स्वास्थ्य दोनों पर प्रत्यक्ष और गंभीर प्रभाव पड़ता है। यहां यह भी एक तथ्य है कि वैश्विक स्तर पर वर्ष 2019 में लगभग 53.6 मिलियन टन ई-कचरा उत्पन्न हुआ था, जो लगभग 7.3 किलोग्राम प्रति व्यक्ति था ।आज भारत समेत दुनिया भर में बहुत बड़ी मात्रा में इलैक्ट्रोनिक कचरा पैदा हो रहा है। एक आंकड़े के अनुसार भारत ने वर्ष 2019 में लगभग 3.2 मिलियन टन ई-कचरा उत्पन्न किया, जिसमें से लगभग 90% कचरे का विवरण उपलब्ध नहीं है। वास्तव में इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उत्पादन में वृद्धि को औद्योगीकरण और शहरीकरण के लिये ज़िम्मेदार ठहराया गया है, जिसके परिणामस्वरूप अन्य इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की माँग में वृद्धि हुई है। इतना ही नहीं, बढ़ता हुआ तकनीकी विकास, उच्च खपत दर, विभिन्न इलैक्ट्रोनिक उत्पादों के जीवन चक्र का कम होना, खराब हुए इलैक्ट्रोनिक उपकरणों को ठीक करने के विकल्पों का कम होना, बढ़ता इलैक्ट्रोनिकीकरण, डिजाइन में कमियां और ई-कचरे का सही प्रबंधन नहीं होना जैसे प्रमुख कारण भी हैं ।हाल फिलहाल, यदि हम यहां भारत के इलैक्ट्रोनिक कचरे से संबंधित आंकड़ों की बात करें तो भारत वर्तमान में विश्व स्तर पर ई-कचरा पैदा करने वाले सबसे बड़े देशों में तीसरे स्थान पर है, जो केवल चीन और अमेरिका से पीछे है। भारत में ई-कचरे की मात्रा 2021-22 में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ 1.6 मिलियन टन हो गई है। उल्लेखनीय है कि भारत के 65 शहर कुल ई-कचरे का 60% से अधिक उत्पन्न करते हैं, जबकि 10 राज्य कुल ई-कचरे का 70% उत्पन्न करते हैं। कहना ग़लत नहीं होगा कि आज ई कचरे के ठीक से प्रबंधन नहीं होने, ई कचरे के ठीक से एकत्रीकरण नहीं किए जाने तथा उसका पुनर्चक्रण नहीं होने के कारण धरती के अनेक मूल्यवान संसाधन बर्बाद हो रहे हैं और इससे दुनिया भर के समुदायों के लिए प्रदूषण का खतरा लगातार बढ़ रहा है। क्या यह गंभीर और संवेदनशील नहीं है कि आज अनौपचारिक पुनर्चक्रण प्रथाओं के कारण हर साल पर्यावरण में 58,000 किलोग्राम पारा और 45 मिलियन किलोग्राम ब्रोमीनयुक्त अग्निरोधी प्लास्टिक छोड़ा जाता है ? यह भी एक तथ्य है कि ई-कचरे के पुनर्चक्रण से भी दुर्लभ पृथ्वी तत्व की मांग का केवल 1% ही पूरा हो पाता है ।ग्लोबल ई-वेस्ट मॉनिटर 2024 की रिपोर्ट में कहा गया है कि संग्रहण और पुनर्चक्रण की प्रलेखित दर 2022 में 22.3% से घटकर 2030 तक 20% हो जाएगी, जिसका कारण दुनिया भर में ई-कचरे के उत्पादन में हो रही भारी वृद्धि के सापेक्ष पुनर्चक्रण प्रयासों में बढ़ता अंतर है। बहरहाल, रिपोर्ट के अनुसार यूरोप में ई-कचरे के औपचारिक संग्रहण और पुनर्चक्रण की उच्चतम दर (42.8%) है, जबकि अफ्रीका में ई-कचरा कम मात्रा में उत्पन्न होने के बावजूद पुनर्चक्रण की दर एक प्रतिशत से भी कम है। यहां यह भी एक तथ्य है कि एशिया के देश विश्व का लगभग आधा ई-कचरा (30 अरब किलोग्राम) उत्पन्न करते हैं , लेकिन अपेक्षाकृत उनमें से बहुत कम ने कानून बनाए हैं या स्पष्ट ई-कचरा संग्रहण लक्ष्य निर्धारित किए हैं। कहना ग़लत नहीं होगा कि भारत सहित एशिया, वैश्विक ई-कचरे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उत्पन्न करता है , लेकिन ई-कचरा प्रबंधन में उसने सीमित प्रगति की है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार यूरोप (17.6 किग्रा), ओशिनिया (16.1 किग्रा) और अमेरिका (14.1 किग्रा) ने 2022 में प्रति व्यक्ति सबसे अधिक ई-कचरा उत्पन्न किया। हालांकि, इन देशों में प्रति व्यक्ति संग्रहण और पुनर्चक्रण दर भी सबसे अधिक दर्ज की गई है। मसलन, यूरोप में प्रति व्यक्ति 7.53 किग्रा, ओशिनिया में प्रति व्यक्ति 6.66 किग्रा तथा अमेरिका में प्रति व्यक्ति 4.2 किग्रा की दर है और इसके पीछे कारण

उनका संग्रहण और पुनर्चक्रण बुनियादी ढांचा सबसे उन्नत होना बताया गया है। कहना ग़लत नहीं होगा कि स्क्रीन तथा मॉनिटर, खिलौने, माइक्रोवेव ओवन, वैक्यूम क्लीनर और ई-सिगरेट, छोटे आईटी और दूरसंचार उपकरण - लैपटॉप, मोबाइल फोन, जीपीएस डिवाइस और राउटर काफी मात्रा में ई-कचरा पैदा करने के लिए जिम्मेदार हैं। रिपोर्ट बताती है कि खिलौने, माइक्रोवेव ओवन, वैक्यूम क्लीनर और ई-सिगरेट विश्व के ई-कचरे का एक तिहाई (20 बिलियन किलोग्राम) हिस्सा हैं, इनके लिए पुनर्चक्रण दर वैश्विक स्तर पर बहुत कम 12% है। वहीं दूसरी ओर छोटे आईटी और दूरसंचार उपकरण- लैपटॉप, मोबाइल फोन, जीपीएस डिवाइस और राउटर -5 बिलियन किलोग्राम ई-कचरे पैदा करते हैं, जबकि इसका केवल 22% ही औपचारिक रूप से एकत्रित और पुनर्चक्रित किया गया है। आज विश्व में 81 देशों ने ई-कचरा नीति, कानून या विनियमन अपनाया है। भारत में भी ई-कचरे से निपटने के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं। मसलन, वर्ष 2011 में, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 द्वारा शासित ई-कचरा (प्रबंधन और हैंडलिंग) विनियम 2010 से संबंधित एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया गया था। इतना ही नहीं, ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 पेश किए गए, जिसके अंतर्गत 21 से अधिक उत्पाद शामिल किए गए हैं। इसमें कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप (सीएफएल) और अन्य पारा युक्त लैंप, तथा अन्य उपकरण शामिल थे। यह भी उल्लेखनीय है कि भारत सरकार ने ई-कचरा (प्रबंधन) नियम, 2022 को अधिसूचित किया है , जिसका मुख्य उद्देश्य ई-कचरा प्रबंधन प्रक्रिया को डिजिटल बनाना और दृश्यता बढ़ाना है। यह विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के विनिर्माण में खतरनाक पदार्थों (जैसे सीसा, पारा और कैडमियम) के उपयोग को भी प्रतिबंधित करता है, जिनका मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अंत में यही कहूंगा कि ई-कचरे से हमारे इको-सिस्टम के असंतुलन के साथ ही जल, वायु, भूमि व मृदा और रेडियोसक्रिय प्रदूषण में भी वृद्धि हो रही है। हालांकि यह भी एक तथ्य है कि ई कचरे में सोना, चाँदी, कोबाल्ट और प्लैटिनम के साथ-साथ अन्य दुर्लभ धातुएँ प्राप्त की जा सकती हैं ।एक अध्ययन के अनुसार सामान मात्रा में चाँदी अयस्क की अपेक्षा ई-कचरे से अधिक मात्रा में चाँदी प्राप्त की जा सकती है। एक अध्ययन यह भी बताता है कि एक टन सोने के अयस्क की तुलना में एक टन स्मार्ट फोन में 100 गुना अधिक सोना होता है। ई-कचरे का समाधान यह है कि इसके लिए एक वर्तुलाकार अर्थव्यवस्था बनाई जाए ।आज जरूरत इस बात की है इलैक्ट्रोनिक प्रोडक्ट्स को इस तरह से डिजाइन किया जाए कि उनका रि-यूज किया जा सके तथा उनकी रिसाइक्लिंग भी संभव हो सके। 'बाय-बैक' या 'रिटर्न ऑफर' जैसी योजनाएँ ई-कचरा कम करने में लाभकारी साबित हो सकती हैं। विभिन्न समावेशी नीतियों, तरीकों को अपनाकर तथा रिसाइक्लिंग प्रोसेस को बेहतर बनाकर, जागरूक व सचेत रहकर ई-कचरे की समस्या से निपटा जा सकता है।

सुनील कुमार महला,
फ्रीलांस राइटर, कालमिस्ट व युवा साहित्यकार, उत्तराखंड।

केंद्रीय बजट में नहीं होगी दिल्ली से जुड़ी कोई घोषणा, चुनाव आयोग ने किया साफ; कहा- कैबिनेट सेक्रेटरी को पत्र लिखेंगे

एक फरवरी को केंद्र सरकार अपना बजट पेश करेगी। मगर इस बजट में दिल्ली से जुड़ा कोई एलान नहीं होगा। भारत निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को यह स्पष्ट कर दिया है। आयोग कैबिनेट सेक्रेटरी को एक पत्र भी लिखेगा। दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों पर पांच फरवरी को मतदान है। आठ फरवरी को मतगणना होगी। तीन दिन बाद यानी 10 जनवरी से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा के पांच फरवरी को होने वाले चुनाव को देखते हुए चुनाव आयोग ने साफ किया है कि एक फरवरी को आने वाले केंद्रीय बजट में दिल्ली से जुड़ी कोई घोषणा नहीं होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने मंगलवार को कहा कि आज ही वह कैबिनेट सेक्रेटरी को इस संबंध में चिट्ठी लिखेंगे और कहेंगे कि वह यह सुनिश्चित करें कि दिल्ली को लेकर कोई नई घोषणा न की जाए।

मुख्य चुनाव आयुक्त ने यह जानकारी मंगलवार को चुनाव आचार संहिता और सभी राजनीतिक दलों के लिए एक समान चुनावी मौके मुहैया कराने को लेकर पूछे गए सवालों के जवाब में दी है।

उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों के एक लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया कराने के लिए सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को भी साफ निर्देश दिया गया है। इसमें अनुमति से लेकर कार्रवाई करने तक में एकरूपता की बात कही गई है।

हेलीकॉप्टर जांच पर क्या कहा?

आयोग ने पिछले चुनाव में कुछ राजनीतिक दलों की ओर से सिर्फ उनके ही हेलीकॉप्टर की जांच के आरोपों का भी जवाब दिया और कहा कि आयोग ऐसा बिल्कुल नहीं करता है। वह सभी दलों के साथ एक समान व्यवहार करता है।

चुनावी डेकोरम बनाकर रखें राजनीतिक दलः आयोग

आयोग ने राजनीतक दलों को चुनावी प्रक्रिया का अहम हिस्सा बताया और कहा कि चुनावी विश्वसनीयता बनी रहे और नई पीढ़ी चुनाव में बढ़चढ़कर हिस्सा ले इसके लिए जरूरी है कि राजनीतिक दल चुनावी डेकोरम को बनाए रखे। खासकर प्रचार के दौरान वह कोई ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी न करें, जिससे चुनावी प्रक्रिया को लेकर उनके मन किसी तरह कुंठा न पैदा हो।

जल्द ही 100 करोड़ मतदाता होंगे देश में

चुनाव आयोग ने बताया कि देश में जल्द ही मतदाताओं की संख्या 100 करोड़ होने वाली है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि देश में मतदाताओं की संख्या 99 करोड़ हो गई है। यह आंकड़े तब आए है, जब देश में मतदाता सूची की पुनरीक्षण का पहला चरण पूरा हो गया है। जो पांच जनवरी को उत्तर प्रदेश सहित देश के कई राज्यों में पूरा हो गया है, जल्द ही बाकी राज्यों में यह काम पूरा हो जाएगा।

दिल्ली चुनाव को त्रिकोणीय बना रहे कांग्रेस के तेवर, ब्रेक लगाने की कोशिश में जुटी आप

भारत निर्वाचन आयोग ने दिल्ली विधानसभा चुनावों का एलान कर दिया है। पांच फरवरी को मतदान और आठ फरवरी को मतगणना होगी। भाजपा के अलावा कांग्रेस ने सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। कांग्रेस के तीखे तेवरों से दिल्ली का सियासी रण त्रिकोणीय हो चुका है। मगर आप इन हमलों को नरम करने की कोशिश में जुटी है।

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली के चुनावी तारीखों का एलान होने के साथ ही मैदान में मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कांग्रेस की लगातार तेज होती सियासी मुहिम से बेचैन आम आदमी पार्टी कांग्रेस हाईकमान को साधने की कोशिश में जुट गई है। समझा जाता है कि आप नेतृत्व की ओर से अनौपचारिक राजनीतिक चैनलों के जरिए दिल्ली कांग्रेस की आप सरकार और अरविंद केजरीवाल पर किए जा रहे हमलों को नरम करने के लिए समझाने से लेकर दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

क्यों टाली गई माकन की प्रेस कॉन्फ्रेंस?

कांग्रेस की ओर से आप को अभी इस बारे में किसी तरह की गुंजाइश देने का कोई संकेत नहीं दिया गया है। मगर विपक्षी खेमे के अनौपचारिक राजनीतिक चैनलों की पहल का यह असर ही है कि केजरीवाल के खिलाफ आक्रामक मोर्चा खोलने वाले कांग्रेस के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अजय माकन की रविवार को प्रस्तावित प्रेस कॉन्फ्रेंस टाल दी गई।

आप सरकार पर हमला बोलते हुए अजय माकन ने अरविंद केजरीवाल पर राष्ट्र विरोधी होने का आरोप लगाते हुए बीते शनिवार एलान किया था कि वे रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबूतों के साथ इसका खुलासा करेंगे।

संपर्क साधने की कोशिश में आप

माकन ने अपने एक्स पोस्ट पर इस प्रस्तावित प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानकारी भी साझा की। अपने केंद्रीय नेतृत्व के मजबूत समर्थन से भाजपा की निरंतर बढ़ती घेरेबंदी के बीच माकन के साथ संदीप दीक्षित और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव की तिकड़ी के आक्रामक तेवरों से गहराती चुनावी चुनौतियों की बेचैनी में ही आप ने कांग्रेस हाईकमान से संपर्क साधने का प्रयास किया।

आप और कांग्रेस में अभी सीधी बात नहीं

हालांकि अनौपचारिक राजनीतिक चैनल से जुड़े विपक्षी खेमे के सूत्रों के अनुसार कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व और आप नेताओं के बीच कोई सीधी बातचीत अभी तक नहीं हो पायी है, न ही पार्टी हाईकमान ने दिल्ली की अपनी चुनावी रणनीति में बदलाव के कोई संकेत दिए हैं। लेकिन इतना जरूर हुआ कि माकन ने कुछ अन्य वजह देते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस टाल दी पर तीखे तेवर अभी नहीं छोड़े हैं।

चुनाव आयोग की ओर से पांच फरवरी को दिल्ली में मतदान कराने की घोषणा के तत्काल बाद माकन ने आप सरकार और केजरीवाल पर तीखे प्रहार करते हुए एक्स पोस्ट में कहा लिखा कि आप ने एक दशक से ऊपर सरकार चलाई और उस दौर में दिल्ली ने विकास से दूरी बनाई। मुख्यमंत्री और एलजी की हुई लड़ाई, और शराब घोटाले की बू भी आई। दिल्ली वाले नहीं सहेंगे विकास से दूरी।

ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोय, औरन को शीतल करे आपहुं शीतल होय

आओ सोच समझकर अपनी राय बनाएं, वाणी बोले
किसी भी विषय वस्तु पर अपनी राय बनाते, शब्दों का चयन करते समय विवेकपूर्ण हाजिर मंथन ज़रूरी
जीवन में छोटी-छोटी बातें विभित्सक रूप धारण कर सकती है, इसलिए निर्णय से पहले सटीकता परखना जरूरी - एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र

गोंदिया - विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत पूरी दुनियाँ में बेबाकी से अपनी राय रखने के लिए जाना जाता है, क्योंकि यह आवाज 142.6 करोड़ जनसांख्यिकीयतंत्र की आवाज़ होती है इसलिए पूरी दुनियाँ के प्रमुख व्यक्तित्व गंभीरता से भारत के बयानों पर ध्यान देकर उसका उचित विवेकपूर्ण मंथन कर सकारात्मक समझ निकालते हैं।हालांकि अपवाद स्वरूप कुछ देश ऐसे भी हैं जो भारत की बातों को विवादों में भी ले जाने की कोशिश करते हैं। हम भारत माता के वंशज हैं। संस्कृति, सभ्यता हमारे लहू में समाई हुई है। हम दैनिक जीवन में भी अपनी राय बेबाकी से रखने में विश्वास रखते हैं क्योंकि हम लोकतंत्र की छत्रछाया में रहने के आदी हैं, परंतु हम में से कई लोग ऐसे भी हैं जो अपनी राय बनाने में गंभीर नहीं हैं बिना सोचे समझे बयान बाजी, राय देना सलाह देना, किसी भी बात का नकारात्मक मतलब निकालना, बिना बात के झगड़ा बढ़ाना, सहनशीलता संवेदनशीलता और सहिष्णुता की कमी के कारण जीवन में छोटी-छोटी बातों का परिणाम विभित्सक रूप धारण कर लेता है जिससे हमारी जान के लाले भी पड़ जाते हैं इसलिए हमें चाहिए कि किसी भी विषय वस्तु, बात,स्थिति पर अपनी राय बनाते,शब्दों का चयन करते 1 समय विवेकपूर्ण हाजर मंथन कर उस बात को रखना अपेक्षाकृत सटीक होगा, उस राय की सटीकता का विचार भी कुछ पलों में कर नपी तुली समझ का परिचय देना जरूरी है। चूंकि हम वैश्विक स्तरपर भारत की राय और भारत माता के सपूतों की राय प्रकट करने की बात कर रहे हैं, इसीलिए आज हम इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे आओ सोच समझकर अपनी राय बनाए, वाणी बोले।

साथियों बात अगर हम अनेक मुद्दों पर मनीषियों की राय की करें तो दरअसल, हर मुद्दे को लेकर सबकी राय अलग अलग होती है, ऐसे में कई लोग सही तरह से राय व्यक्त न कर पाने के कारण भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं, तो कुछ लोग दिलचस्प तरीके से अपनी बात रखकर भीड़ से अलग पहचान बनाने में कामयाब हो जाते हैं,आमतौर पर हर चीज को लेकर सभी लोगों कि अपनी अपनी राय होती हैं, ऐसे में ज्यादातर लोग नुक्कड़ पर राजनीतिक चर्चा से लेकर सामाजिक मुद्दों पर विचार-विमर्श करने और घरेलू मामलों में अपनी राय देने से पीछे नहीं हटते हैं। हालांकि, इस दौरान कुछ लोगों की राय भीड़ से बिल्कुल अलग होती है. वहीं अगर हम चाहें तो कुछ इंप्रेसिव तरीकों से अपनी राय को सबसे अलग बना सकते हैं।

साथियों कई बार जल्दी जल्दी में राय देने के चक्कर में हम अपनी बात को सही तरीके से पेश नहीं कर पाते हैं, ऐसे में न सिर्फ हम सामने वाले को अपनी बात समझाने में असफल हो जाते हैं बल्कि सामने बैठे लोग हमारी बात का गलत मतलब भी निकाल सकते हैं, इसलिए हमें अपनी राय रखने से पहले शब्दों का चुनाव काफी सोच-समझ कर ही करना है। वैसे तो हर मुद्दे पर सभी का अलग राय होती है, वहीं राय सही या गलत भी हो सकती है, मगर राय रखते समय कई लोग अपनी बात को इतने खास अंदाज में बयां करते हैं कि हम चाहकर भी उनकी बात का विरोध नहीं कर पाते हैं। हालांकि, अगर हम चाहें तो राय देने के इस दिलचस्प तरीके को अपनी व्यक्तित्व में भी शामिल कर सकते हैं।

साथियों बात अगर हम राय देने में शब्दों के चयन की करें तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी हमें शब्दों का चयन सोच समझ कर करना चाहिए, चाहे किसी से बात करने के क्रम में हो या किसी समारोह में या किसी वाद विवाद में। ऐसा माना जाता है कि हथियार या चोट के घाव तो भर जाते हैं पर शब्दों के घाव हमेशा ताजा रहते हैं। किसी मित्र की टांग खिंचाई में बड़ा मजा आता है पर ऐसा करने में हम इतने मशगूल हो जाते हैं कि कुछ अनचाहा कह जाते हैं।

साथियों बात अगर हम राय देने में शब्दों के चयन की करें तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी हमें शब्दों का चयन सोच समझ कर करना चाहिए, चाहे किसी से बात करने के क्रम में हो या किसी समारोह में या किसी वाद विवाद में। ऐसा माना जाता है कि हथियार या चोट के घाव तो भर जाते हैं पर शब्दों के घाव हमेशा ताजा रहते हैं। किसी मित्र की टांग खिंचाई में बड़ा मजा आता है पर ऐसा करने में हम इतने मशगूल हो जाते हैं कि कुछ अनचाहा कह जाते हैं। कुछ ऐसा ही क्रोध के समय भी होता है। इसीलिए क्रोध के समय अप्रिय बातें करने से बचना चाहिए। इसके अलावा यदि किसी को सलाह दी जाए तो इस बात का ध्यान रखा जाए कि हमारे शब्दों से उसके आत्मसम्मान को ठेस ना पहुंचे। यदि सही शब्दों का चयन किया जाए तो आदेश भी निवेदन लगेगा और बिना किसी के अहम को ठेस पहुंचे सब का काम हो जाएगा।

साथियों इसके साथ ही हमें अपने कहे गए शब्दों की जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। चाहे अनचाहे यदि आपकी बातों से किसी की भावनाएं आहत हो तो हमें उन बातों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, ना कि तरह-तरह के बहाने बनाकर अपनी बातों को सिद्ध करना चाहिए। ऐसा करके हम अनावश्यक बहस से निजात पा सकेंगे और सामने वाले के मन में भी सम्मान के पात्र बनेंगे। वास्तव में हमारे शब्द हमारे हृदय की प्रेम की अभिव्यक्ति हैं। अब यह हमारे ऊपर है कि हम इस प्रेम को संसार में लुटाएं या प्रेम की जगह घृणा फैलाएं। प्रेम पूर्वक की गई आलोचना किसी को सही मार्ग पर ला सकती है या अप्रिय शब्दों से युक्त अच्छी सलाह उसे गलत रास्ते को चुनने की ओर प्रेरित कर सकती है। इसलिए हमें शब्दों के खजाने को निरंतर बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि इनका प्रयोग संसार में खुशियां बांटने में किया जा सके।अतएव सोच समझकर शब्दों का चयन करें।

साथियों बात अगर हम अपनी राय शाब्दिक अभिव्यक्ति के बाद तीसरे सबसे कीमती सोने पर सुहागा वाणी की करें तो, कबीर दास जी का यह दोहा और उसका अर्थ सबने सुना होगा, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोय,औरन को शीतल करे आपहुं शीतल होय,हम सब इसका अर्थ भी जानते हैं पर हम में से ऐसे कितने हैं जो इन पर अपनी मौजूदा जिंदगी में अमल करते हैं। यह सिर्फ एक दोहा नहीं है,एक फिलॉसफी है कि हम अपने शब्द का चुनाव सोच समझकर करें। आखिर शब्द ही हैं जो दोस्त को दुश्मन और दुश्मन को दोस्त बनाने की काबिलियत रखते हैं। द्रौपदी के कहे तीखे शब्द, जो उसने दुर्योधन को कहे, महाभारत के युद्ध का एक कारण बने। दूसरी तरफ दुर्योधन के शब्दों ने कर्ण को अपना मित्र बना लिया। यह दिखाता है कि किस प्रकार शब्द अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हम बिना सोचे-समझे किसी की बात को गलत कह देते हैं, क्या यह कहना इतना आसान होता है, बिना यह जाने कि पूरी बात क्या है?

साथियों एक प्रख्यात कहावत के कुछ इस तरह बोल हैं:शब्द तीर की तरह होते हैं, एक बार जुबान की कमान से निकल गए तो आप उन्हें दोबारा वापिस नहीं ले सकतें।हम बिना सोचे समझे किसी की बात को गलत कह देते हैं- आखिर क्यों ? क्योंकि हम समझने के लिए नहीं बल्कि प्रतिक्रिया देने के लिए सुनते हैं। हम मन ही मन धारणाएं बना लेते हैं और हमारी प्रतिक्रियाओं के साथ तैयार होते हैं। हम सामने वाले की बातों को समझकर नहीं सुनते। और इसकी कई वजहें हैं जिनके बारे में मैं इस उत्तर में नहीं समझा सकतीं।

अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर उसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि आओ सोच समझ कर अपनी राय बनाएं, वाणी बोले। किसी भी विषय वस्तु पर अपनी राय बनाते, शब्दों का चयन करते समय विवेकपूर्ण हाजिर मंथन जरूरी है। जीवन में छोटी-छोटी बातें विभित्सक रूप धारण कर सकती है इसलिए निर्णय से पहले सटीकता परखना जरूरी है।

महाकुंभ जाने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर, यहां पर बनेगा प्राइवेट बसों का पहला बस अड्डा

गाजियाबाद में पहली बार निजी बसों के लिए बस अड्डा बनेगा। यात्रियों के लिए एसी बिना एसी और डबल डेकर बसों का संचालन होगा। कोई भी व्यक्ति निजी बस अड्डे से प्रयागराज के लिए बसों का संचालन कर सकता है। यात्रियों के लिए वेटिंग स्थान सर्दी से बचने की व्यवस्था पेयजल पूछताछ केंद्र शौचालय मोबाइल चार्जिंग प्वाइंट बस प्लेटफार्म सूचना बोर्ड आदि सुविधाएं दी जाएंगी।

गाजियाबाद। महाकुंभ मेले के मद्देनजर पहली बार केवल निजी बसों के लिए जिले में बस अड्डा बनेगा। यात्रियों के लिए जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। एसी, बिना एसी और डबल डेकर बसों का संचालन होगा। कोई भी व्यक्ति निजी बस अड्डे से प्रयागराज के लिए बसों का संचालन कर सकता है। अभी तक जिले में निजी बसों के लिए एक भी अधिकारिक बस अड्डा नहीं है। काफी संख्या में लोग रोडवेज की बजाय निजी बस में यात्रा करते हैं। यात्री आनलाइन निजी बस में सीट बुक कर लेते हैं। लंबी दूरी की निजी बस में यात्रा करने के लिए ज्यादातर लोगों को दिल्ली का रुख करना पड़ता है। जिले में निजी बसों का आधिकारिक बस अड्डा नहीं है। शहीद स्थल मेट्रो स्टेशन के पास और मोहन नगर में निजी बसें अवैध रूप से सड़क पर खड़ी होती हैं। बड़ी संख्या में लोग महाकुंभ मेले में प्रयागराज जाएंगे। शासन स्तर से निजी स्तर पर बसों के संचालन का आदेश दिया गया है। संभागीय परिवहन विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। विभाग ने इस संबंध में डीएम को पत्र लिखा है।

जिला प्रशासन निजी बस अड्डे के लिए भूमि उपलब्ध कराएगा। भूमि मिलने के बाद उस पर यात्रियों के लिए सुविधा उपलब्ध बराई जाएगी। यात्रियों के लिए वेटिंग स्थान, सर्दी से बचने की व्यवस्था, पेयजल, पूछताछ केंद्र, शौचालय, मोबाइल चार्जिंग प्वाइंट, बस प्लेटफार्म, सूचना बोर्ड आदि सुविधाएं दी जाएंगी।

परिवहन निगम चलाएगा 600 बसें

परिवहन निगम गाजियाबाद रीजन की 600 बसों को कुंभ मेले में भेजने की तैयारी कर रहा है। महाकुंभ से पहले जिले को 100 सीएनजी व 38 ई-बसें मिलनी थी। शासन से भी बसें अलाट हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक भी बसें नहीं मिल सकी हैं। अभी तक एक भी बस गाजियाबाद रीजन को नहीं मिली है।

150 से अधिक चालकों की कमी

महाकुंभ मेला शुरू होने से पहले रोडवेज बसों में चालकों की कमियों को भी दूर किया जाना था। संविदा पर भर्ती होनी थी, लेकिन अभी तक जरूरत के हिसाब से भर्ती नहीं की गई है। गाजियाबाद रीजन में अभी 150 से अधिक चालकों की कमी हैं। अकेले कौशांबी डिपो बस अड्डे से प्रदेश भर के शहरों के लिए रोजाना 30 से 40 हजार यात्री सफर करते हैं।

धारा 163 लागू, पुलिस ने जारी किए ये दिशा-निर्देश; जानिए क्या हैं प्रमुख बिंदु

गाजियाबाद पुलिस ने आगामी त्योहारों और गणतंत्र दिवस को देखते हुए जनपद में धारा 163 लागू की है। इसके तहत पुलिस ने दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं। जिनमें सार्वजनिक स्थल पर पांच या पांच से अधिक लोग बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के धरना जुलूस और प्रदर्शन के लिए एकत्र नहीं होंगे। आगे विस्तार से जानिए आखिर क्या-क्या निर्देश जारी किए गए हैं।

गाजियाबाद। आगामी त्योहारों और गणतंत्र दिवस को देखते हुए कमिश्नरेट पुलिस ने जनपद में धारा 163 लागू की है। इसके तहत पुलिस ने दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं। जिनमें सार्वजनिक स्थल पर पांच या पांच से अधिक लोग बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के धरना, जुलूस और प्रदर्शन के लिए एकत्र नहीं होंगे।

जिले में इसलिए लागू की गई धारा 163

अतिरिक्त पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएएनएस)-2023 की धारा 163 के तहत मंगलवार से निषेधाज्ञा लागू की है। आने वाले दिनों में 14 जनवरी को मोहम्मद हजरत अली का जन्मदिन एवं मकर संक्रांति पर्व, 24 जनवरी को जननायक कर्पूरी ठाकुर का जन्मदिवस, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, दो फरवरी को वसंत पंचमी, 12 फरवरी को संत रविदास जयंती, 14 फरवरी को शब-ए-बारात हैं। इन्हें देखते हुए पुलिस ने लोगों के लिए कई दिशा निर्देश भी जारी किए हैं।

पुलिस ने इन प्रमुख बिंदुओं पर जारी किए निर्देश

कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार अस्त्र-शस्त्र, विस्फोटक पदार्थ या ऐसी वस्तु जिनका प्रयोग आक्रमण किये जाने में किया जा सकता है जैसे चाकू, भाला, बरछी, तलवार, छुरा आदि लेकर नहीं चलेगा और न ही इनको किसी स्थान पर एकत्रित करेगा और न ही इनका सार्वजनिक प्रदर्शन करेगा।

कमिश्नरेट गाजियाबाद में किसी भी गांव अथवा मोहल्ले में ऐसे व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जायेगा, जिसके जाने से उस क्षेत्र में तनाव की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना हो।

सार्वजनिक स्थल व अपने घर की छत पर किसी प्रकार की ईटें, पत्थर, किसी भी प्रकार की मिटटी, कांच की बोतलें, सोडा वाटर की बोतलें एवं कोई भी ऐसा ज्वलनशील पदार्थ एकत्रित नहीं किया जा सकता

कोई भी होटल/धर्मशाला आदि का प्रबन्धक/मालिक किसी भी व्यक्ति को बिना उसकी पहचान सत्यापित कराये बिना कमरा आवंटित नहीं करेगा।

परीक्षा केंद्रों की एक किमी की परिधि में फोटोकापी मशीन एवं स्कैनर का संचालन परीक्षा अवधि में प्रतिबंधित है।

कोई भी व्यक्ति या समूह यातायात जाम नही करेगा और न ही बाधित करेगा। किसी भी सरकारी अथवा गैर सरकारी कार्मिक को ड्यूटी पर जाने से नही रोकेगा।

राजकीय कार्यालयों के ऊपर व आसपास एक किमी की परिधि में ड्रोन से शूटिंग करना प्रतिबंधित। अन्य स्थानों पर संबंधित पुलिस उपायुक्त के बिना किसी प्रकार की ड्रोन कैमरे से शूटिंग या फोटोग्राफी नहीं की जायेगी।

सरकार द्वारा पालिथीन, प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा होने के कारण इनका प्रयोग नहीं किया जाएगा।

डिजिटल डाटा संरक्षण अधिनियम 2023 लागू करने की कवायद शुरू-नियमावली 2025 का मसौदा जारी-18 फ़रवरी 2025 तक सार्वजनिक परामर्श आमंत्रित

वर्तमान प्रौद्योगिकी युग में डिजिटल पर्सनल डाटा संरक्षण बिल डेटा सुरक्षा में मील का पत्थर साबित होगा
मोबाइल में कोई ऐप इंस्टॉल करते समय जो हम कई तरह की इजाजत देते हैं,डीपीडीपी कानून व नियमावली के जरिए सटीक प्रोटेक्शन मिलेगा- एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र

गोंदिया - वैश्विक स्तरपर वर्तमान प्रौद्योगिकी युग में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा का अति खास महत्व हो गया है अगर यह हमारे डाटा चोरी होते हैं,या किसी के हाथ लगते हैं तो हम भारी मुसीबत में फंस सकते हैं या भारी हानि उठानी पड़ सकती है, इसे सुरक्षित रखने के लिए यह कानून 2023 व नियमावली 2025 हमारे लिए बहुत सुरक्षित संरक्षण है। बता दे वह सारा डेटा जो हम ऑनलाइन देते हैं, वह डिजिटल पर्सनल डेटा होता है।डिजिटल पर्सनल डेटा समझने के लिए हम एक उदाहरण की मदद ले सकते हैं। जब भी हम अपने मोबाइल में कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं तो उसके लिए हमको कई तरह की इजाजत देनी पड़ती हैं,इसके तहत आपको कैमरा, गैलरी, कॉन्टैक्ट और जीपीएस जैसी चीजों के एक्सेस देने होते हैं।इसके बाद उस ऐप के पास हमसे जुड़ा बहुत सारा पर्सनल डेटा पहुंच जाता है, बशर्ते उन्हें पता होता है कि हमारे कॉन्टैक्ट्स में किस- किस के नंबर हैं,हमारे फोन में कौन सी फोटो और वीडियो हैं,यहां तक कि जीपीएस की मदद से वह हमारे मूवमेंट को भी ट्रैक कर सकते हैं,कई बार देखा गया है कि कुछ ऐप लोगों के पर्सनल डेटा को अपने सर्वर पर अपलोड कर लेते हैं और फिर उसे दूसरी कंपनियों को बेच देते हैं। हमें यह जानकारी ही नहीं होती है कि हमारा डेटा कहां- कहां इस्तेमाल हो रहा है।इस बिल के जरिए इसी तरह के पर्सनल डेटा को प्रोटेक्शन मिलेगी, चूँकि वर्तमान प्रौद्योगिकी युग में डिजिटल पर्सनल डाटा संरक्षण बिल डेटा सुरक्षा में मील का पत्थर साबित होगा, इसलिए आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे, डिजिटल डाटा संरक्षण अधिनियम 2023 लागू करने की कवायद शुरू, नियमावली 2025 का मसौदा जारी, 18 फरवरी 2025 तक सार्वजनिक परामर्श आमंत्रित।

साथियों बात अगर हम डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटक्शन नियमावली 2025 के मसौदे को समझने की करें तो,इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफोर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के लिए ड्राफ्ट रूल्स पेश किए हैं, जिसमें यूजर डेटा का कलेक्शन, स्टोरेज और यूज़र्स डेटा की प्रोसेसिंग के नियमों के बारे में जानकारी दी गई है, इस डॉक्यूमेंट में डेटा की प्राइवेसी, सिक्योरिटी और खासतौर पर बच्चों के डेटा से संबंधित भी नए प्रावधान शामिल है,इसके अलावा, यह नए नियम सहमति और डेटा उल्लंघन की सूचनाओं के लिए भी एक फ्रेमवर्क स्थापित करते हैं।यह कानून अगस्त 2023 में भारतीय संसद से पारित किया गया था, और फिलहाल सरकार इन ड्राफ्ट रूल्स पर 18 फरवरी 2025 तक सार्वजनिक प्रतिक्रियाएं प्राप्त कर रही है। इस आर्टिकल के माध्यम से सरकार के इस डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के लिए पेश किए गए ड्राफ्ट रूल्स को सरल शब्दों में समझते हैं।डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (डीपीडीपी) - ड्राफ्ट नियम, 2025 (1) सूचना और सहमति, सूचनाः यूज़र्स के पर्सनल डेटा को मैनेज करने वाले व्यक्ति या संस्था को डेटा फिड्यूशियरी कहा जाता है। सरकार के नए नियमों के मुताबिक, अब से डेटा फिड्यूशियरी को यूजर का डेटा कलेक्ट करने से पहले उन्हें सूचना देनी होगी, इसमें उन सभी पर्सनल डेटा की लिस्ट दी जाएगी, जो इकट्ठा की जा रही है, इसके अलावा यूज़र्स को यह भी बताया जाएगा कि उन पर्सनल डेटा को इकट्ठा करना क्यों जरूरी है और उनका उपयोग कैसे किया जाएगा।स्पष्ट सहमतिः डेटा इकट्ठा करने से पहले कंपनियों को आपकी स्पष्ट सहमति प्राप्त करनी होगी, ताकि हम यह पूरी तरह से समझ सकें कि हमारा डेटा किस उद्देश्य से और कैसे उपयोग होगा,सहमति वापस लेने का अधिकारःहम अपनी सहमति कभी भी, जितनी आसानी से दी थी, उतनी ही आसानी से वापस ले सकते हैं, इस नियम के मुताबिक कंपनियां हमारी सहमति यानी कंसेंट को वापस लेने के लिए प्रक्रिया को जटिल या भ्रमित करने की कोशिश नहीं कर सकती,कंसेंट मैनेजरः कम से कम 2 करोड़ रुपये की नेट वर्थ वाला, भारत में रजिस्टर्ड एक कंसेंट मैनेजर, हमारी सहमति को मैनेज और रिकॉर्ड करेगा। कंसेंट मैनेजर एक सर्टिफाइड इंटरऑपरेबल प्लेटफ़ॉर्म प्रदान करेगा और सिक्योरिटी प्लान्स को सुनिश्चित करेगा (2) डेटा कलेक्शन एंड सिक्योरिटी-कम से कम डेटा कलेक्ट करनाः कंपनियां सिर्फ वही डेटा एकत्र कर सकती हैं, जो जरूरी हो, और एनक्रिप्शन, एक्सेस कंट्रोल और डेटा बैकअप्स आदि एक बार डेटा का उद्देश्य पूरा हो जाए तो कंपनियों को वो डेटा डिलीट करना होगा। सिक्योरिटी का नियमः कंपनियों ने यूज़र्स के पर्सनल डेटा को सुरक्षित रखने के लिए उचित सुरक्षा उपायों जैसे एनक्रिप्शन, एक्सेस कंट्रोल और डेटा बैकअप्स आदि सुनिश्चित करना होगा,इसका उद्देश्य अन ऑफिशियल एक्सेस या उल्लंघन से बचा जा सके।(3) बच्चों का डेटा, बच्चों के लिए विशेष नियमः कंपनियों को किसी बच्चे का व्यक्तिगत डेटा प्रोसेस करने से पहले माता-पिता या कानूनी अभिभावक से वेरीफाइड कंसेंट प्राप्त करना अनिवार्य होगा। डेटा फिड्यूशियरी को सरकारी डॉक्यूमेंट्स (आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट आदि) या डिजिटल टोकन्स का उपयोग करके माता- पिता की पहचान करनी होगी। बच्चों के लिए प्राइवेसी रूल्सः सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और वेबसाइट्स पर बच्चों की पहचान सरकार द्वारा जारी किए पहचान पत्रों (आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट आदि) या डिजिटल टोकन के जरिए वेरीफाई करनी होगी।किसे मिलेगी छूटः अनुसूची IV में बताए गए नियमों के मुताबिक शैक्षिक संस्थाएं और बाल कल्याण संगठन बच्चों के डेटा से संबंधित कुछ प्रावधानों से छूट प्राप्त कर सकते हैं। (4) डेटा उल्लंघन और क्रॉस-बॉर्डर डेटा ट्रांसफर डेटा उल्लंघनकी सूचनाः यदि कोई डेटा उल्लंघन होता है, तो कंपनी को प्रभावित व्यक्तियों और डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड को तुरंत सूचित करना होगा। प्रभावित व्यक्तियों को सूचना में उल्लंघन, इसके संभावित परिणाम और उसे ठीक करने के उपायों के बारे में जानकारी दी जाएगी।क्रॉस- बॉर्डरडेटा ट्रांसफरः अगर डेटा प्राप्त करने वाला देश निर्धारित डेटा सिक्योरिटी रूल्स को पूरा करता है तो केंद्रीय सरकार की अनुमति के बाद ही क्रॉस-बॉर्डर डेटा ट्रांसफर होगा (5) सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशियरी और कॉन्टैक्ट डिटेल्स सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशियरी : एसडीएफ ऐसे बड़े संस्थान होते हैं, जो भारी मात्रा में संवेदनशील डेटा को हैंडल करते हैं, उन्हें वार्षिक डेटा प्रोटेक्शन इम्पैक्ट असेसमेंट, ऑडिट्स करने होंगे और यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके एल्गोरिदम डेटा प्रिंसिपल्स को नुकसान न पहुंचा पाएं। कॉन्टैक्ट डिटेल्सः डेटा फिड्यूशियरी को अपनी वेबसाइट्स और ऐप्स पर डेटा से संबंधित सवालों के लिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स पब्लिश करना होगा, इसमें डेटा प्रोटेक्शन अधिकारी (यदि लागू हो) या आधिकारिक प्रतिनिधि की कॉन्टैक्ट डिटेल्स शामिल होगी।(6) डेटा प्रिंसिपल्स के अधिकार डेटा प्रिंसिपल्स को अपने व्यक्तिगत डेटा तक एक्सेस प्राप्त करने और उसे मिटाने का अधिकार होगा,इसके लिए उन्हें डेटा फिड्यूशियरी से संपर्क करना होगा और इस प्रक्रिया का पालन करना होगा,डेटा फिड्यूशियरी को इन अधिकारों का उपयोग करने के लिए स्पष्ट प्रक्रिया और शिकायत को समाधान करने के लिए समय सीमा बतानी होगी।(7) राज्य की जिम्मेदारियां और प्रवर्तन। राज्य द्वारा डेटा का उपयोगः राज्य को व्यक्तिगत डेटा का सही तरीके से, खास उद्देश्य के लिए औरसुरक्षित रखते हुए उपयोग करना होगा। डेटा को ज्यादा देर तक नहीं रखना चाहिए।लोगों कोजानकारी दी जानी चाहिए और सवाल पूछने के लिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिया जाना चाहिए। सिलेक्शन कमेटीः इस कमेटी का काम बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों के लिए उम्मीदवारों की सिफारिश करना है, जो डीपीडीपी नियमों, 2025 का पालन सुनिश्चित करेंगे।डेटा कलेक्शन बोर्डः सरकार द्वारा बनाए गए नए नियमों के ड्राफ्ट में उल्लंघनों की जांच और सजा देने के लिए डेटा कलेक्शन बोर्ड बनाने की बात भी कही गई है. यह बोर्ड एक डिजिटल ऑफिस की तरह काम करेगा, जहां रिमोट हियरिंग और आसान प्रक्रियाएं होंगी।

साथियों बात अगर हम डिजिटल संरक्षण अधिनियम 2023 के बारे में जानने की करें तो, डिजिटल पर्सनलडेटा प्रोटेक्शन बिल को संसद के दोनों सदन से मंजूरी मिल चुकी है,राष्ट्रपति द्रौपदी मूर्मू नें उनकी मंजूरी देकर हस्ताक्षर कर दिए हैं कानून का रूप ले लिया है।इस कानून को कब से लागू किया जाएगा इसका नोटिफिकेशन अलग से लागू किया जाएगा। इस कानून के लागू होने के बाद लोगों को अपने डेटा कलेक्शन, स्टोरेज और प्रोसेसिंग के बारे में जानकारी मांगने का अधिकार मिल जाएगा। डिजिटल सर्विस का इस्तेमाल करने वाले लोगों को यह कानून ज्यादा अधिकार देता है.बता दें कि इस बिल में नियमों का उल्लंघन करने पर कम से कम 50 करोड़ रुपये और अधिकतम 250 करोड़ रुपये जुर्माने का प्रावधान है।

अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि डिजिटल डाटा संरक्षण अधिनियम 2023 लागू करने की कवायद शुरू- नियमावली 2025 का मसौदा जारी-18 फ़रवरी 2025 तक सार्वजनिक परामर्श आमंत्रित।वर्तमान प्रौद्योगिकी युग में डिजिटल पर्सनल डाटा संरक्षण बिल डेटा सुरक्षा में मील का पत्थर साबित होगा।मोबाइल में कोई ऐप इंस्टॉल करते समय जो हम कई तरह की इजाजत देते हैं, डीपीडीपी कानून व नियमावली के जरिए सटीक प्रोटेक्शन मिलेगा।

भारत मोबिलिटी 2025 में पेश होगी मारुति ई विटारा, जानिए मारुति की पवेलियन में दिखेंगी और कौन-सी कार

परिवहन विशेष न्यूज

मारुति सुजुकी ने भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 में दिखाई जाने वाली कारों की लिस्ट का खुलास कर दिया है। इसके साथ ही कंपनी ने Bharat Mobility 2025 के विजन को बारे में भी बताया है। Auto Expo 2025 में मारुति अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार Maruti e Vitara को पेश करेगी। इसके साथ ही कंपनी अपनी Dzire Swift Invicto Jimny Fronx Grand Vitara और Brezza मॉडल को भी दिखाएगी।

नई दिल्ली। भारत की सबसे बड़ी ऑटो निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड (MSIL) ने भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 में पेश होने वाली गाड़ियों का खुलासा कर दिया है। Bharat Mobility Global Expo 2025 के लिए कंपनी ने अपने थीम का नाम 'e For Me' रखा है। इसके तहत कंपनी इलेक्ट्रिक कारों को शोकेस करेगी। आइए जानते हैं कि Maruti Suzuki की तरफ से Auto Expo 2025 में कौन-सी गाड़ियां दिखाई जाने वाली है।

Bharat Mobility 2025 में मारुति की कारें

भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 में मारुति अपने 'ई फॉर मी' विजन के तहत पहली ईबॉर्न एसयूवी को पेश करेगी, जो ई विटारा है। इसे यहां पर पेश किया जाएगा। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है, जिसकी तरफ भारतीय ग्राहकों को अट्रैक्ट किया जा सकें। इसके साथ ही, मारुति की पवेलियन में Dzire, Swift, Invicto, Jimny, Fronx, Grand Vitara और Brezza जैसे पॉपुलर मॉडल को भी प्रदर्शित किया जाएगा।

हमारा 'ई फॉर मी' विजन भारत के इलेक्ट्रिक मोबिलिटी परिवर्तन में एक निर्णायक क्षण का प्रतिनिधित्व करता है। जबकि मारुति सुजुकी चार दशकों से अधिक समय से भारत का भरोसेमंद मोबिलिटी पार्टनर रहा है, आज हम इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए एक क्रांतिकारी दृष्टिकोण पेश

कर रहे हैं जो ग्राहक को केंद्र में रखता है। यह रणनीति सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहन लॉन्च करने से कहीं आगे जाती है - यह एक संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के बारे में है जो हर भारतीय के लिए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में बदलाव को स्वाभाविक और सहज बनाता है। हम आगामी भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 में 'ई फॉर मी' के संपूर्ण आयाम को प्रदर्शित करने के लिए उत्साहित हैं, जहाँ आगंतुक सीधे अनुभव करेंगे कि हम भारत में मोबिलिटी के भविष्य की कल्पना कैसे कर रहे हैं।

पार्थो बनर्जी, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के मार्केटिंग और सेल्स के वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी

Maruti e Vitara के फीचर्स

ई-विटारा में ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, पैनोरमिक सनरूफ, फ्रंट सीट्स के लिए वेंटिलेशन, हेड-अप डिस्प्ले, वायरलेस फोन चार्जर और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसे फीचर्स देखने के लिए मिलेंगे।

इसमें पैसेंजर की सेफ्टी के लिए छह एयरबैग्स, 360-डिग्री कैमरा, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक के साथ ऑटो-होल्ड, और लेवल-2 ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) जैसे एडवांस फीचर्स से लैस किया जा सकता है। मारुति की यह पहली कार होने वाली है, जिसमें ADAS फीचर देखने के लिए मिलेगा।

ई-विटारा को दो बैटरी पैक 49 kWh और 61 kWh के साथ पेश किया जाएगा। जिसे देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि इसकी रेंज 600 किमी तक रहने वाली है।

सोनी-होंडा की पहली इलेक्ट्रिक कार Afeela 1 EV लॉन्च, सिंगल चार्ज में देगी 480km तक का रेंज

परिवहन विशेष न्यूज

Afeela 1 EV की प्री-रिजर्वेशन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसकी बुकिंग के लिए ग्राहकों को करीब $200 (लगभग 17000 रुपये) का प्री-पेमेंट करना होगा। यह कार 2025 में कैलिफोर्निया में उपलब्ध होगी और इसकी डिलीवरी 2026 के बीच से शुरू हो सकती है। इसमें कई बेहतरी फीचर्स दिए गए हैं। आइए जानते हैं कि Afeela 1 EV किन फीचर्स से लैस है।

नई दिल्ली। वर्तमान में लास वेगास में कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो (CES) 2025 का आयोजन हो रहा है। इस ऑटो शो में सोनी होंडा मोबिलिटी ने अपनी Afeela 1 EV को पेश किया है। दोनों ने मिलकर अपहली पहली इलेक्ट्रिक कार Afeela 1 EV को पेश किया है। इसे कई बेहतरीन फीचर्स और स्मार्ट तकनीक के साथ लेकर आया गया है। इनसे ड्राइवर और पैसेंजर को बेहतर एक्सपीरिएंस मिलता है। आइए जानते हैं कि यह किन खास फीचर्स के साथ आती है।

1. मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस

Afeela 1 में 40 से ज्यादा सेंसर का लगाया गया है, जो इसे एडवांस ड्राइवर असिस्ट सिस्टम (ADAS) का हिस्सा बनाते हैं। यह आपको सेफ और परेशानी के बिना ड्राइविंग का एक्सपीरिएंस देती है। इसमें Qualcomm Technologies का Snapdragon डिजिटल चेसिस का इस्तेमाल किया गया है, जो कनेक्टेड कार के फीचर्स को और भी स्मार्ट बनाता है।

2. लंबी रेंज और शानदार परफॉर्मेंस

सोनी होंडा मोबिलिटी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि Afeela 1 EV एक बार फुल चार्ज होने के बाद 300 किलोमीटर तक की रेंज देती है। जिसकी वजह से यह ग्लोबल मार्केट में प्रमुख EV कंपनियों जैसे टेस्ला और रिवियन के साथ मुकाबला करती दिखेगी।

3. किफायती कीमत

Afeela 1 की कीमत 89,900 डालर (लगभग 77 लाख रुपये) से शुरू होती है। इसे दो दो ट्रिम्स में लेकर आया गया है, जो ओरिजिन और सिग्नेचर है। इसके सिग्नेचर ट्रिम में 21 इंच के पहिए, रियर एंटरटेनमेंट सिस्टम, और सेंटर कैमरा मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इसके Afeela 1 सिग्नेचर ट्रिम की कीमत 102,900 डॉलर (लगभग 88 लाख रुपये) है।

4. रिसाइकिल चीजों से है बनी

Afeela 1 के 70 फीसदी पार्ट्स को रिसाइकिल की गई चीजों से बनाया गया है, जो पर्यावरण के सुरक्षा को बढ़ाते हैं। इसके अलावा, कार के बॉडी के निर्माण में रिसाइकिल की गई मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है।

5. स्मार्ट एक्सपीरिएंस

इसमें 3D मोशन मैनेजमेंट सिस्टम दिया गया है, जो सड़क की सतह पर आरामदायक सवारी और बेहतर हैंडलिंग देती है। इसके अलावा, सोनी की 360 स्पैटियल साउंड सिस्टम दिया गया है, जो कार के केबिन में शानदार साउंट का एक्सपीरिएंस देता है।

6. सेफ्टी और सेंसर्स

अफीला 1 में 40 से अधिक सेंसर लगाए गए हैं, जिसमें कैमरे, LiDAR, रडार और अल्ट्रासोनिक सेंसर जैसे फीचर्स शामिल है। ये सेंसर मिलकर ADAS के लिए जरूरी जानकारी प्रदान करते हैं, जो सेफ और स्मार्ट ड्राइविंग एक्सपीरिएंस देते हैं।

2025 में Ducati की 14 Bikes होंगी लॉन्च, सुपरस्पोर्ट्स बाइक से लेकर रेट्रो मोटरसाइकिल तक शामिल

परिवहन विशेष न्यूज

साल 2025 में भारतीय बाजार में डुकाटी तकरीनब 14 मोटरसाइकिल लॉन्च करने जा रही है। इसके लिए कंपनी की तरफ मॉडलों का खुलासा भी कर दिया गया है। साथ ही इन बाइक के लॉन्च का टाइमलाइन को भी जारी कर दिया गया है। इन बाइक में रेट्रो लुक वाली बाइक से लेकर सुपर बाइक तक रहने वाली है।

नई दिल्ली। Ducati इंडिया ने साल 2025 में लॉन्च होने वाली मोटरसाइकिलों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट के मुताबिक, भारत में साल 2025 में 14 मोटरसाइकिल लॉन्च होगी। भारत में लॉन्च होने जा रही डुकाटी की मोटरसाइकिल की लिस्ट में सुपरबाइक से लेकर रेट्रो लुक वाली बाइक तक शामिल रहने वाली है। आइए जानते हैं कि साल 2025 में Ducati की कौन-कौन सी बाइक भारत में लॉन्च होने वाली है।

Ducati की ये मोटरसाइकिल होंगी लॉन्च

भारत में लॉन्च होने वाली डुकाटी मोटरसाइकिल की लिस्ट में पैनिगेल V4 7वीं जनरेशन, डुकाटी डेजर्टएक्स डिस्कवरी, अपडेटेड V2 लाइनअप शामिल होगा जिसमें पैनिगेल, स्ट्रीटफाइटर और मल्टीस्ट्राडा V2 शामिल है। इसके साथ ही, तीसरी जनरेशन की स्ट्रीटफाइटर V4 और स्क्रैम्बलर डार्क 2nd जनरेशन भी साल 2025 में लॉन्च होगी।

इसके अलावा भारत में डुकाटी की डुकाटी डायवेल, पैनिगेल V2 फाइनल एडिशन, पैनिगेल V4 ट्राइकोलोर इटालिया, पैनिगेल V4 ट्राइकोलोर और स्क्रैम्बलर रिजोमा को भी लॉन्च किया जाएगा।

साल 2025 में Ducati Bikes की लॉन्च टाइमलाइन

Panigale V4 7th Generation - जनवरी से मार्च 2025 के बीच।

Ducati DesertX Discovery - जनवरी से मार्च 2025 के बीच।

Panigale V2 Final Edition - अप्रैल से जून 2025 के बीच।

Scrambler 2G Dark- अप्रैल से जून 2025 के बीच।

Multistrada V2- जुलाई से सितंबर 2025 के बीच।

Scrambler Rizoma - जुलाई से सितंबर 2025 के बीच।

Streetfighter V4 3rd Generation - जुलाई से सितंबर 2025 के बीच।

Streetfighter V2 - जुलाई से सितंबर 2025 के बीच।

Panigale V2 - जुलाई से सितंबर 2025 के बीच।

किन शहरों में कर सकते हैं डुकाटी की बाइक बुक?

Ducati बाइक की चाहत रखने वाले कोच्चि, हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता, चंडीगढ़ और अहमदाबाद जैसे शहरों में डीलरशिप के जरिए मोटरसाइकिल की बुकिंग कर सकते हैं।

कंपनी की तरफ से खुलासा किया गया है कि साल 2025 में वह भारत में बिल्कुल नई बाइक लॉन्च करेंगे। अभी तक कंपनी की तरफ से इसका खुलासा नहीं किया गया है कि वह कौन सा मॉडल होगा। इसलिए साल 2025 में देखने लायक बड़ा सरप्राइज देखने के लिए मिल सकता है। अनुमान लगाया जा रहा है कि डुकाटी मॉन्स्टर के 30 एनिवर्सरी एडिशन में से किसी एक को लॉन्च कर सकती है। साल 2025 में डुकाटी 14 मोटरसाइकिल को लॉन्च करने के साथ ही अपने डीलरशिप नेटवर्क को बढ़ाने की भी योजना बना रही है। भारत में लॉन्च होने वाली मोटरसाइकिल में EICMA 2024 में पेश की गई अपडेटेड स्ट्रीटफाइटर V2 और पैनिगेल V2 भी शामिल है, जिसका इंतजार लंबे समय से किया जा रहा है।

भारत मोबिलिटी 2025 में लॉन्च होंगी ये इलेक्ट्रिक कारें और एसयूवी, मिलेंगे बेहतरीन फीचर्स और रेंज

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। जनवरी 2025 में भारत में कारों का मेला लगने जा रहा है। इस दौरान कई बेहतरीन कारों और एसयूवी को लॉन्च किया जाएग। जानकारी के मुताबिक Bharat Mobility 2025 के दौरान कौन सी कंपनी की ओर से कौन सी Electric Cars and SUVs को लॉन्च (Bharat Mobility 2025 EV Launch) करने की तैयारी की जा रही है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

MG Cyberster

ब्रिटिश वाहन निर्माता MG मोटर्स की ओर से भारतीय बाजार में जल्द ही नई इलेक्ट्रिक सुपर कार के तौर पर MG Cyberster को लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। कंपनी की ओर से इस गाड़ी को Bharat Mobility 2025 में लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा कंपनी की ओर से MG Mifa9 Electric MPV को भी शोकेस किया जाएगा। जिसे बाद में भारत में लॉन्च किया जा सकता है।

Maruti E-Vitara

मारुति की ओर से भी भारत मोबिलिटी 2025 के दौरान अपनी पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी के तौर पर Maruti E-Vitara को लॉन्च (Upcoming SUVs in 2025) किया जाएगा। इस गाड़ी को सुजुकी की ओर से EICMA 2024 के दौरान पहली बार शोकेस किया गया था। वहीं इसके कॉन्सेप्ट वर्जन को मारुति ने जनवरी 2023 में हुए ऑटो एक्सपो के दौरान दिखाया था।

Hyundai Creta EV

हुंडई की ओर से भी कम कीमत वाली इलेक्ट्रिक एसयूवी के तौर पर Hyundai Creta EV को लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। उम्मीद की जा रही है कि इसे भी भारत मोबिलिटी 2025 में आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया जाएगा। इसके इलेक्ट्रिक वर्जन का डिजाइन भी ICE वेरिएंट की तरह ही होगा।

Tata Harrier EV

टाटा मोटर्स भी भारत मोबिलिटी 2025 के दौरान Tata Harrier EV को लॉन्च कर देगी। कंपनी की ओर से इस एसयूवी के इलेक्ट्रिक वर्जन को 2024 में हुए मोबिलिटी एक्सपो के दौरान भी शोकेस किया गया था। इस एसयूवी में भी अन्य एसयूवी की तरह कई बेहतरीन फीचर्स को दिया जाएगा और इसका डिजाइन इसके ICE वर्जन से मिलता जुलता होगा।

Tata Sierra EV

टाटा की ओर से मोबिलिटी के दौरान एक और इलेक्ट्रिक एसयूवी Tata Sierra EV को भी लॉन्च किया जा सकता है। कंपनी की ओर से इसके कॉन्सेप्ट वर्जन को जनवरी 2023 में हुए ऑटो एक्सपो के दौरान दिखाया जा चुका है। लेकिन इसके प्रोडक्शन वर्जन को इलेक्ट्रिक और ICE दोनों ही सेगमेंट में लाया जाएगा।

Mahindra XUV 3XO EV

महिंद्रा भी भारत मोबिलिटी 2025 के दौरान अपनी कॉम्पैक्ट एसयूवी Mahindra XUV 3XO के Electric वर्जन को ला सकती है। हालांकि इसे अभी सिर्फ पेश किया जा सकता है, लेकिन साल के मध्य तक इसे आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया जाएगा।

2024 में आटोमोबाइल की खुदरा बिक्री में 9% की वृद्धि, दोपहिया वाहनों की बिक्री में 11% की बढ़ोतरी

परिवहन विशेष न्यूज

पिछले साल पैसेंजर वाहन की बिक्री 4073843 इकाई रही जो 2023 में 3873381 इकाई की तुलना में पांच प्रतिशत अधिक है। दोपहिया वाहनों की बिक्री साल दर साल 11 प्रतिशत बढ़कर 2024 में 18912959 इकाई हो गई जबकि 2023 में यह 17072932 इकाई थी। तिपहिया वाहनों का पंजीकरण साल दर साल 11 प्रतिशत बढ़कर 2023 के 1105942 इकाई के मुकाबले 1221909 इकाई हो गया।

नई दिल्ली। चुनौतीपूर्ण कारोबारी माहौल के बीच दोपहिया और यात्री वाहनों की मजबूत मांग के दम पर 2024 में आटोमोबाइल खुदरा बिक्री में सालाना आधार पर नौ प्रतिशत की वृद्धि हुई। पिछले साल कुल वाहन पंजीकरण 2,61,07,679 इकाई रहा, जबकि 2023 कैलेंडर वर्ष में यह 2,39,28,293 यूनिट था। फेडरेशन आफ आटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (फाडा) के प्रेसिडेंट सीएस विग्नेश्वर ने कहा कि वर्ष 2024 में कई चुनौतियों, जैसे गर्मी, केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर चुनाव और असमान मानसून के बावजूद आटो खुदरा उद्योग लचीला बना रहा।

साल 2024 में इन वजहों से बढ़ी बिक्री

इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि दोपहिया खंड में बेहतर आपूर्ति, नए माडल और मजबूत ग्रामीण मांग ने विकास को गति दी। हालांकि वित्तीय बाधाओं और बढ़ती ईवी प्रतिस्पर्धा ने चुनौतियां पेश करना जारी रखा। विग्नेश्वर ने कहा कि यात्री वाहन (पीवी) खंड को मजबूत नेटवर्क विस्तार और उत्पाद लांच से लाभ हुआ। हालांकि अधिक इन्वेंट्री के कारण मार्जिन पर दबाव रहा, जिससे दूसरी छमाही में छूट की होड़ मच गई। उन्होंने कहा कि चुनाव से प्रेरित अनिश्चितता और बुनियादी ढांचे पर खर्च में कमी के कारण वाणिज्यिक वाहन खंड का प्रदर्शन धीमा रहा।

पिछले साल हुई इतनी बिक्री

पिछले साल पैसेंजर वाहन की बिक्री 40,73,843 इकाई रही, जो 2023 में 38,73,381 इकाई की तुलना में पांच प्रतिशत अधिक है। दोपहिया वाहनों की बिक्री साल दर साल 11 प्रतिशत बढ़कर 2024 में 1,89,12,959 इकाई हो गई, जबकि 2023 में यह 1,70,72,932 इकाई थी। तिपहिया वाहनों का पंजीकरण साल दर साल 11 प्रतिशत बढ़कर 2023 के 11,05,942 इकाई के मुकाबले 12,21,909 इकाई हो गया। ट्रैक्टर की बिक्री साल दर साल तीन प्रतिशत बढ़कर 8,94,112 इकाई रही। वहीं वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री 2024 में 10,04,856 इकाई पर स्थिर रही।

December 2023 में कितनी बिक्री

बीते साल December महीने में देशभर में कुल 2007042 यूनिट्स वाहनों की बिक्री हुई थी। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इस साल December महीने में 12.49 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है। बीते साल दो पहिया वाहन सेगमेंट में 1454353 यूनिट्स की बिक्री हुई थी। यात्री वाहन सेगमेंट में 299351, तीन पहिया सेगमेंट में 98384, कमर्शियल सेगमेंट में 76010 और ट्रैक्टर सेगमेंट में 78944 यूनिट्स की बिक्री हुई थी।

शहरी नियोजन में पदयात्रियों और साइकल सवारों की चिंता जरूरी, योजनाएं केवल कारों को ध्यान में रखकर न बनाई जाएं

परिवहन विशेष न्यूज

देश के शहरों में पदयात्रियों के लिए सबसे बड़ा जोखिम और असुविधा के कारण लोग चलने के लिए निर्धारित फुटपाथ अवैध कब्जों अतिक्रमण टूट-फूट और कुप्रबंधन के शिकार हैं। इसकी वजह से लोग सड़कों पर चलने के लिए विवश होते है। बड़े शहरों में एक एकीकृत मेट्रोपोलिटन ट्रांसपोर्ट अथारिटी हो जो एक स्वायत्त संस्थान होगा जिसके दायरे में शहरी परिवहन के सभी घटक-मेट्रो बस कैब सभी आएंगे।

नई दिल्ली। शहरों में सुधार के तौर-तरीके सुझाने के लिए गठित की एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति ने मोटर वाहन कानून में संशोधन करके पैदल चलने वालों और साइकल सवारों को भी ट्रैफिक की परिभाषा में शामिल करने का सुझाव दिया है। समिति का विचार है कि शहरों में ट्रैफिक के संदर्भ में नीतियां बनाने में कारों के बजाय पदयात्रियों और साइकल सवारों की सुविधा और सुरक्षा पर ध्यान होना चाहिए। समिति ने दो खंडों में अपनी सिफारिशें शहरी कार्य मंत्रालय को सौंपी हैं। साबरमती रिवर फ्रंट के प्रमुख रहे केशव वर्मा की अध्यक्षता वाली समिति ने कहा है कि पैदल चलने का सुरक्षित वातावरण एक शहर के सुचारु संचालन के लिए एक जरूरी गुण है।

पदयात्रियों और साइकल सवारों को भी मिले महत्व

शहरों के लिए योजना बनाने में उन 42 प्रतिशत लोगों की अनदेखी बिल्कुल भी नहीं की जा सकती, जो शहरों में जोखिम से भरी सड़कों पर पैदल चलते हैं। शहरों का नियोजन समावेशी होना चाहिए। इसमें उतना ही महत्व पदयात्रियों और साइकल सवारों को दिया जाना चाहिए जो कारों और दूसरे वाहनों को ट्रैफिक में मिलता है। समिति ने इस पर आश्चर्य जताया है कि मोटर वाहन कानून में ट्रैफिक की परिभाषा में पैदल चलने वाले और साइकल सवार क्यों शामिल नहीं हैं।

इन वजहों से सड़कों पर लोग चलने को मजबूर

समिति की यह सिफारिश इसलिए बेहद अहम है, क्योंकि देश के शहरों में पदयात्रियों के लिए सबसे बड़ा जोखिम और असुविधा का कारण यह रहा है, क्योंकि उनके चलने के लिए निर्धारित फुटपाथ अवैध कब्जों, अतिक्रमण, टूट-फूट और कुप्रबंधन के शिकार हैं। इनके अभाव में मजबूरी में लोग सड़कों पर चलने के लिए विवश होते है। समिति ने कहा है कि शहरों को इस तरह डिजाइन किया जाना चाहिए कि उनमें पूर्ण सड़कें (सभी के लिए सुगम और सुविधाजनक) हों। समिति ने पंजाब का भी उदाहरण दिया है, जहां पहली बार सड़कों की योजना बनाने में पैदल चलने के अधिकार को भी शामिल किया गया है। इसका अर्थ है कि सड़कों के नए निर्माण अथवा उन्हें चौड़ा करने की योजनाओं में फुटपाथ की व्यवस्था को अनिवार्य किया गया है। कर्नाटक भी इसी दिशा में काम कर रहा है। उसने इससे संबंधित मसौदे पर लोगों की प्रतिक्रियाएं आमंत्रित की हैं।

मेट्रोपोलिटन ट्रांसपोर्ट अथारिटी का हो गठन

समिति ने इसके साथ ही बड़े शहरों में एक एकीकृत मेट्रोपोलिटन ट्रांसपोर्ट अथारिटी के गठन का भी सुझाव दिया है यह एक स्वायत्त संस्थान होगा, जिसके दायरे में शहरी परिवहन के सभी घटक-मेट्रो, बस, कैब सभी आएंगे। शहरों के ढांचे में सुधार के लिए केंद्र सरकार ने हाल ही में राज्यों के अधिकारियों और विशेषज्ञों को शामिल करते हुए पांच उपसमूहों का भी गठन किया है। इनकी रिपोर्ट और इसके साथ ही केशव वर्मा की अध्यक्षता वाले विशेषज्ञों के पैनल की रिपोर्ट के आधार पर शहरों के प्रशासन में बड़े पैमाने पर बदलाव की तैयारी की जा रही है। शहरी नियोजन से जुड़े एक अधिकारी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शहरों में सुधार के लिए आमूल-चूल परिवर्तन की बात कही है। इसकी दिशा में काम किया जा रहा है। सभी उपसमूहों की रिपोर्ट फरवरी के अंत तक आ जाने की उम्मीद है। इसके बाद नए कार्यक्रमों का एलान किया जाएगा।

परीक्षा के दौरान माता-पिता की भूमिका

विजय गर्ग

माता-पिता और बच्चों के बीच हर समय बातचीत होना बहुत जरूरी है। माता-पिता के पास जीवन के अनुभवों के साथ-साथ अपने बच्चों के बेहतर भविष्य की योजनाएं भी होती हैं। ये दोनों बातें हर गरीब और अमीर माता-पिता में देखी जाती हैं। अलग बात यह है कि वे इन चीजों को अपने तरीके से करते हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में माता-पिता के पास अपने बच्चों को देने के लिए समय नहीं है, वहीं भारी-भरकम सिलेबस के कारण बच्चे थके हुए नजर आते हैं। परीक्षाओं कानजदीक आते ही शिक्षक बच्चों को अधिक अंक लाने के लिए प्रोत्साहित कर उन पर दबाव बनाने लगते हैं। समय-समय पर अभिभावकों को बच्चों की रिपोर्ट से अवगत कराने से बच्चे की शिक्षा की स्थिति पहले ही साफ हो जाती है। स्पष्ट शब्दों में, स्कूल स्टाफ अपना हिस्सा लेता है या अपनी आय का आधा बोझ साझा करता है। कुछ निजी स्कूलों में स्कूल प्रबंधन बच्चों को अतिरिक्त समय देकर भी तैयारी कराना चाहता है, लेकिन बच्चों के समय से पहले या बाद में चले जाने की समस्या सामने आती है ।ट्यूशन पढ़ने जाने के समय में तालमेल न होने के 5 कारण, ज्यादातर माता-पिता सहमत नहीं दरअसल, जैसे-जैसे परीक्षाएं नजदीक आती हैं ये सारी चीजें बच्चों पर मानसिक दबाव डालती हैं, जबकि अब समय है बच्चों को मानसिक दबाव में आने से बचाने का। माता-पिता चाहे कामकाजी हों या घर पर रहते हों, उनके बच्चों को इस समय बहुत कुछ चाहिए। माता-पिता चलते-चलते भी बच्चों से एक ही बात कहते हैं- पढ़ाई करो और परीक्षा की तैयारी करो। ले लोगे तो कुछ बन जायेगाबाद में पढ़ाई की जिम्मेदारी पिता ही संभालते हैं या फिर डरा-धमकाकर बच्चे में डर पैदा किया जाता है। बच्चे के स्कूल से घर लौटने, फिर घर से ट्यूशन और ट्यूशन से घर लौटने तक माता-पिता की ज़िम्मेदारी बोझिल होती है, जबकि जिन चीज़ों में बच्चे को माता-पिता की ज़रूरत होती है, उन्हें नज़रअंदाज कर दिया जाता है। जैसे-जैसे परीक्षाएं नजदीक आती हैं, माता-पिता को बच्चों के प्रति सौहार्दपूर्ण रवैया अपनाना चाहिए और उनसे हल्के-फुल्के माहौल में बात करनी चाहिए। उनकी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश कर रहा हूंः करणसाथ ही, बच्चा पढ़ाई के प्रति किस तरह की मानसिकता रखता है, क्या वह अपने भविष्य को लेकर गंभीर है या नहीं, अधिक अंक आने पर वह क्या करने की सोचता है या कम अंक आने से वह निराश है और क्या वह कुछ गलत भी नहीं कर रहा है ? एक कदम उठाने के बारे में सोच रहा हूँ. माता-पिता के लिए बच्चे के दिमाग का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। विदेश में पढ़ाई के मुद्दे पर बच्चे, शिक्षक और माता-पिता इन चिंताओं से सुरक्षित रहते हैं क्योंकि बच्चे की रुचि के अनुसार उन्हें उसी क्षेत्र में भेजा जाता है, लेकिन हमारे माता-पिता की अपनी रुचि होती है ।अपनी शिक्षा पूरी न कर पाने के कारण वे चाहते हैं कि उनका बच्चा उनका सपना पूरा करे, भले ही बच्चे को इसमें कोई रुचि न हो। माता-पिता, चाहे माता-पिता दोनों कामकाजी हों या कम पढ़े-लिखे हों या अधिक पढ़े-लिखे हों, उन्हें हर समय बस की भूमिका में नहीं रहना चाहिए, उन्हें केवल अच्छे माता-पिता बनना चाहिए, जब बच्चे को कोई समस्या हो तो वह एक दोस्त की तरह माता-पिता को बता सके। . प्रतिष्ठित स्कूलों में दाखिला दिलाना, ऊंची स्कूल फीस देना, अच्छी यूनिफॉर्म खरीदना और महंगी ट्यूशन खाना सिर्फ माता-पिता की जिम्मेदारी नहीं है ।हो गया होता स्कूल में शिक्षक क्या पढ़ाते हैं, बच्चा अच्छा कर रहा है या नहीं, क्लास टेस्ट में अच्छा कर रहा है या नहीं, वह अपने कपड़े कैसे संभालता है, ये छोटी-छोटी बातें उसकी रुचि के बारे में बता सकती हैं खासकर परीक्षा के समय माता-पिता को अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाई करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, बड़े-बड़े लोगों के भाषणों के माध्यम से उनमें यह भावना पैदा करनी चाहिए और बच्चों की हंसी बढ़ानी चाहिए। अनुचित शब्दों का प्रयोग करके उसे अपमानित करेंउसे दिखाने के बजाय, उसे एक छोटे से पाप पर बड़ा होने दें और उसकी हँसी बढ़ाएँ। इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखकर किसी भी बच्चे का भविष्य बचाया जा सकता है।

पानी जैसा जीवन

विजय गर्ग

जैसे पुल पार करने और नदी पार करने में फर्क है, ठीक वैसे ही साल के बीतने और समय के बदलने में भी बहुत बड़ा फर्क है । साल तो हर साल बदल जाता है; समय अदम्य, अडिग और अटल बना रहता है। बीतता है भी या नहीं, एक बड़ा सवाल है। एक समय तो वह है जो दीवार पर टंगी या कलाई पर बंधी घड़ी में है। इस समय का एक रूप है। इसकी एक आवाज है। टिक, टिक, टिक। पर मन के भीतर कौन - सा समय है ? घड़ी वाले समय का तो एक अतीत है, एक भविष्य है। बीच का एक और रास्ता है जिस पर से चलकर वर्तमान गुजरता है। थोड़ा अतीत अपनी पीठ पर लादे और कुछ भविष्य अपने कंधे पर टांगे । इसी बीच के रास्ते को हमने वर्तमान का नाम दिया है। उसमें एक अतीत और एक काल्पनिक भविष्य दोनों का स्वाद होता है। जिसे हम वर्तमान कहते हैं, उसमें बहुत कम वर्तमान होता है । ढेर सारा अतीत और असीमित भविष्य होता है । मन के भीतर तो हमेशा तीनों एक साथ चलते हैं। एक ही पल में अतीत के अवशेष और भविष्य के सपने एक साथ, हाथ थामे चहलकदमी करते हैं। तो फिर भीतर, मन में, समय कहां है? वहां तो सब कुछ गुत्थम- गुत्था है। वहां तो घटनाओं, अनुभवों और स्मृतियों का एक जाल है। समय के किसी भी बिंदु पर हुए सभी अनुभव एक साथ, एक जगह इकट्ठा हो सकते हैं। जैसे कैलेंडर बदलते हैं, बिल्कुल साफ-साफ, वैसे भीतर का समय नहीं बदलता। हर एक तारीख किसी दूसरी तारीख पर सवार होकर चलती है। मन के भीतर समय की चाल बिल्कुल अलग होती है, बाहर बिल्कुल अलग। बाहरी ढांचे में समय ठोस है और मन का समय एक प्रवाह है । उसमें अतीत और भविष्य के बीच कोई स्पष्ट विभाजन नहीं ।

कभी समय की इस गति पर भी विचार किया जाए तो दिलचस्प होगा। हम इसे भी निहारें कि हमारा जीवन किस समय के आधार पर जिया जा रहा है। क्या वह बाहर के व्यवस्थित, ऐतिहासिक समय जैसा है या फिर भीतरी समय जैसा है ? क्या वह शिलाओं - सा ठोस और कठोर है, या फिर पानी जैसा नरम और मुलायम, बगैर किसी आकार का, बगैर किसी हठ और शोक का । इतिहास के अनुभवों ने हमें चट्टान बना दिया है। क्या हम अब किसी नूतन आयाम में प्रवेश कर सकते हैं? क्या हम पानी बन सकते हैं?

लाओत्सू का 'ताओ ते चिंग' दर्शन कहता है कि हमें पानी की तरह रहना चाहिए । जो पानी की तरह हैं, वे किसी प्रतिस्पर्धा में नहीं रहते। सभी का कल्याण चाहते हैं। लाओत्सू का कहना है कि जो पानी की तरह होते हैं वे ऐसी नीची जगहों पर रहते हैं कि उनसे बाकी लोग कमतर करके देखने लगते हैं । दूसरों को अपने से पहले रखते हुए वे फिर भी सबसे आगे हो जाते हैं और सत्य के करीब आ जाते हैं । वे धरती से प्रेम करते हैं । छिछली बातें उन्हें पसंद नहीं। रिश्तों में इन्हें करुणा पसंद होती है। दुनिया में उन्हें शांति पसंद है । वे निंदा और स्तुति से परे हैं। जो जल की तरह है, वह उदार, मुलायम और प्रवाहमान, शुद्ध, पुनर्जीवित करने वाला होता है। पानी की तरह बनना जीवन में सही मार्ग को अपनाना है। पानी का नरम और कोमल होना उसकी कमजोरियां नहीं, वे इसे और अधिक शक्तिशाली बनाती हैं । यह कहीं भी बह सकता है और पत्थर को भी घिस सकता है ।

जिसे हम नया साल कहते हैं, उसमें अगर संभव हो तो अपने जीवन और मतों का परीक्षण करना चाहिए । सुकरात ने यह हिदायत करीब ढाई हजार साल पहले दी थी। उनका मानना था कि जीवन को जाने-समझे बिना जीने का कोई अर्थ नहीं। एथेंस के दार्शनिक ने हर विश्वास की जांच करना अपना मकसद ही बना लिया था, चाहे वह कितना भी प्रचलित क्यों न हो। अक्सर वे लोगों से साहस जैसे गुण को परिभाषित करने के लिए कहते थे, लेकिन बाद में पता चलता था कि जो लोग साहस को सबसे अधिक महत्त्व देते थे, उन्हें पता ही नहीं था कि यह है क्या । केवल अपने जीवन की जांच करके उसमें सुधार की आशा कर सकते हैं। एक बार जिद्दू कृष्णमूर्ति ने लोगों से कहा था कि हम जानते हैं कि सूरज के नीचे कुछ भी नया नहीं है, पर जब हम एक खुशहाल नए साल के बारे में बात करते हैं, तो क्या यह वास्तव में हमारे लिए एक नया साल है ? या यह वही पुराना चलन है जो बार-बार दोहराया जाता है ? इसका मतलब है कि एक ऐसा मस्तिष्क जो अपने संस्कारों, मतों, नतीजों, अपनी विशेषताओं से खुद को मुक्त कर चुका है । हमारा जीवन उथला, सतही और बहुत कम अर्थ वाला है। क्या हम अपने जीवन की पूरी दिशा बदल सकते हैं ? या हम सिर्फ संकीर्ण, घटिया, अर्थहीन जीवन जीने के लिए अभिशप्त हैं ? क्या हम यह सब छोड़ सकते हैं और एक साफ स्लेट के साथ नए सिरे से शुरुआत कर सकते हैं? आमतौर पर लोग नए साल में शराब और संगीत के नशे नृत्य करना और झूमना पसंद करते हैं। जो पसंद है, जो कुछ भी करते आए हैं, उस पर एक मुलायम - सा सवाल भी करें, तो दिलो-दिमाग में नई खिड़कियां खुल सकती हैं । जहां खिड़कियां खुलेंगी, वहां बाद में दरवाजे भी बन सकते हैं। सुख और उत्तेजना के बीच फर्क करना जरूरी है, शोर और संगीत के बीच भी । बेहोशी के सुख और होश में रहने के आनंद को भी समझने की दरकार है। खिड़कियां शिलाओं में नहीं, पानी जैसे जीवन में ही खुल सकती हैं

अध्ययन के समय

विजय गर्ग

स्कूलों के संबंध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के दृष्टिकोण को हासिल करने से पहले कुछ रास्ता तय करना होगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के तहत शिक्षा प्लस के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली ने डेटा प्रदान किया है जो दर्शाता है कि स्कूलों को अभी भी प्रौद्योगिकी में मानकीकृत नहीं किया गया है। केवल 57.2% स्कूलों में कार्यात्मक कंप्यूटर हैं और 53.9% में इंटरनेट की सुविधा है। समसामयिक सन्दर्भ में देखने पर यह तस्वीर धूमिल है, और इसका अर्थ है कंप्यूटर और इंटरनेट की जानकारी रखने वाले युवाओं और इन दोनों से अपरिचित लोगों के बीच विभाजन। बुनियादी ढांचे के मामले में स्थिति बेहतर है, हालांकि आदर्श नहीं हैः 90% स्कूलों में बिजली और लिंग-विशिष्ट शौचालय हैं, लेकिन केवल 52.3% में रेलिंग के साथ रैंप हैं। उत्तरार्द्ध दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति असंवेदनशील समाज का विशिष्ट लक्षण है। लेकिन बिजली की कमी वाले स्कूलों में पाठ पढ़ने की कल्पना करना भी मुश्किल है; स्वाभाविक रूप से, वहां के बच्चों को कंप्यूटर या यहां तक कि उन्नत शिक्षण उपकरणों से कोई परिचित नहीं होगा।

नामांकन और ड्रॉप-आउट मोर्चों पर भी असुविधाजनक खबरें हैं। 2023-24 में, हाल के वर्षों की तुलना में कुल नामांकन में एक करोड़ की गिरावट आई; यह पिछले वर्ष से 37 लाख कम हो गया। हालाँकि प्रारंभिक और मध्य स्तर पर नामांकन अच्छा है, लेकिन बुनियादी स्तर पर और फिर माध्यमिक स्तर पर इसमें तेजी से गिरावट आती है। यह क्षेत्रीय रूप से भिन्न होता है। उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी उल्लेखनीय कमी देखी गई है। बता दें, शून्य नामांकन वाले स्कूलों की संख्या 2,660 बढ़ गई है, जो 2022-23 में 10,294 से बढ़कर 2023-24 में 12,954 हो गई है। यूडीआईएसई प्लस डेटा इन कमियों के कारणों की गहन जांच और इसलिए, उनके सुधार के लिए जगह प्रदान करता है। नामांकन में गिरावट लड़कियों की तुलना में लड़कों के मामले में अधिक है; लड़कों का नामांकन क्यों नहीं हो रहा? ध्यान देने योग्य गिरावट अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यक समुदायों में है; अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के भी कम बच्चों का नामांकन हो रहा है। विश्लेषण से पता चलता है कि प्रवेश के लिए दस्तावेज़ीकरण इन समूहों के लिए नामांकन को कठिन बना देता है। वंचित समूहों के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति प्राप्त करने में आने वाली बाधाएँ भी उतनी ही हतोत्साहित करने वाली हैं; केंद्र सरकार इनके साथ आगे नहीं आ रही है। समाज में असमानताएं एक ऐसी स्थिति है जिस पर प्रवेश और छात्रवृत्ति के लिए विचार किया जाना चाहिए; यदि सभी बच्चों को स्कूल जाना है और वहाँ रहना है तो प्रशासनिक सहायता अपरिहार्य है। जैसे-जैसे कक्षाएँ ऊँची होती जाती हैं, स्कूल छोड़ने की दर बढ़ती जाती है, यह उसी समस्या का एक और पहलू है। सीमांत या वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों को अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के लिए बौद्धिक सहायता - पाठ सुलभ होना चाहिए - और वित्तीय सहायता दोनों की आवश्यकता होती है।

हीटिंग उपकरणों का स्वास्थ्य पर कितना असर

विजय गर्ग

सर्दी का मौसम आते ही खांसी, जुकाम और गले में खराश, कफ, सीने में दर्द, निमोनिया जैसी बीमारियां होना आम है. हालांकि, इससे बचाव जरूरी है, क्योंकि बच्चों और बुजुर्गों पर इसके गंभीर असर हो सकते हैं. इससे निबटने के लिए लोग अक्सर घर के अंदर गर्माहट बनाये रखने के लिए हीटिंग उपकरणों का उपयोग करते हैं. पिछले कुछ वर्षों में इन उपकरणों के उपयोग में तेजी आयी है.

सर्दी का मौसम आते ही खांसी, जुकाम और गले में खराश, कफ, सीने में दर्द, निमोनिया जैसी बीमारियां होना आम है. हालांकि, इससे बचाव जरूरी है, क्योंकि बच्चों और बुजुर्गों पर इसके गंभीर असर हो सकते हैं. इससे निबटने के लिए लोग अक्सर घर के अंदर गर्माहट बनाये रखने के लिए हीटिंग उपकरणों का उपयोग करते हैं. पिछले कुछ वर्षों में इन उपकरणों के उपयोग में तेजी आयी है. अधिकांश हीटरों के अंदर लाल-गर्म धातु की रॉड या सिरेमिक कोर होते हैं. कमरे के तापमान को बढ़ाने के लिए हवा गर्म होकर निकलती है. इस दौरान जलती हुई गर्म धातु हवा में मौजूद पानी को सोख लेती है. इन हीटरों से निकलने वाली हवा गर्म और बेहद रूखी होती है. हीटरों के इस्तेमाल से हमारी त्वचा में रूखापन आने लगता है. घर में हवा में मौजूद ऑक्सीजन भी जल जाती है. इससे कमरे में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जो कई बार जानलेवा भी हो सकती है.

हीटिंग उपकरणों से होनेवाली समस्याएं : पारंपरिक हीटर वाले कमरों में सुस्ती, जी मिचलाना और सिरदर्द जैसी समस्याएं आ सकती हैं. हैलोजन हीटर का उपयोग भी ठीक नहीं है, इससे रेडिएशन का खतरा होता है, साथ ही इन हीटरों से ऐसे रसायन निकलते हैं, जो श्वसन तंत्र को नुकसान पहुंचाते हैं. दमा व एलर्जी से पीड़ति लोगों को इसका अधिक नुकसान होता है. सर्दी के मौसम में घर के अंदर हीटर का नियमित इस्तेमाल करने से बचें, क्योंकि इससे रूम के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ जाता है व आपको घुटन हो सकती है. तापमान में उतार-चढ़ाव से ब्रोंकाइटिस की समस्या हो सकती है. ब्रोंकाइटिस और साइनसाइटिस के मरीजों में एलर्जी की आशंका अधिक होती है. ऐसे रोगियों के फेफड़ों में बलगम जमा हो जाता है, जिसके कारण खांसी और छींक आती है. हीटिंग उपकरणों का इस्तेमाल एलर्जी संभावित लोगों के लिए ठीक नही है, क्योंकि इससे बलगम सूख जाता है और शरीर के अंदर ही रह जाता है. इससे फेफड़े संक्रमित हो सकते हैं और परेशानी बढ़ सकती है.

चेहरे व त्वचा को नुकसान : शुष्क हवा त्वचा को भी नुकसान पहुंचाती है. नमी की कमी से त्वचा पर पपड़ी बनने लगती है. लालीपन आ सकता है. कई बार रैशेज के साथ खून भी बाहर आने लगता है. गैस संचालित होनेवाली सेंट्रल हीटिंग चारों तरफ तेजी से फैलती है. यह बच्चों के फेफड़ों को अधिक नुकसान पहुंचाती है. गैस हीटरों का उपयोग करने वाले घरों में रहने वाले बच्चों को अस्थमा और खांसी, छींकने, घरघराहट के लक्षण देखने को मिलते हैं. इन हीटरों द्वारा छोड़ा जानेवाला कार्बन मोनोऑक्साइड बच्चों व बुजुर्गों को अधिक प्रभावित करता है. गैस हीटर घर में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड के स्तर को बढ़ाते हैं. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से अधिक परेशानी होती है और इसकी वजह से बार-बार अस्थमा का अटैक आता है, फेफड़ों में सूजन और संक्रमण का जोखिम बढ़ जाता है.

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल शैक्षिक स्तंभकार गली कौर चंद एमएचआर मलोट पंजाब

सामाजिक-आर्थिक प्रगति का आधार : भारत की डिजिटल प्रगति !

भारत निरंतर डिजिटल प्रगति की ओर अग्रसर हो रहा है ।भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए मुद्रा और वित्त पर जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत वैश्विक स्तर पर डिजिटल क्रांति में सबसे आगे है। यह हमारे लिए गर्व का विषय है कि आज भारतीय डिजिटल अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई है। विश्व बैंक की ताज़ा रिपोर्ट भारत के तकनीकी विकास की सराहना करती नजर आती है क्यों कि आज भारत की तकनीकी प्रगति विभिन्न रिमोट एरिया (दूर-दराज के क्षेत्रों), विभिन्न छोटे और मंझले उद्यमियों के लिए फायदेमंद साबित होकर अंततः अर्थव्यवस्था को ही मजबूत कर रही है। आंकड़े बताते हैं कि भारत में इंटरनेट की पहुँच वर्ष 2023 में 55 % थी। पिछले तीन वर्षों में इंटरनेट उपयोगकर्ता आधार में 199 मिलियन की वृद्धि हुई है। इतना ही नहीं, भारत में प्रति गीगाबाइट (जीबी) डाटा का मूल्य दुनिया भर में सबसे कम है, जो औसतन 13.32 रुपये प्रति जीबी है। यह भी उल्लेखनीय है कि आज भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा मोबाइल डाटा खपत वाले देशों में से एक है, जहाँ वर्ष 2023 में प्रति उपयोगकर्ता प्रति माह औसत खपत 24.1जीबी रही। कहना ग़लत नहीं होगा कि आज देश का कमजोर वर्ग भी लगातार सशक्त हो रहा है। आंकड़े बताते हैं कि आज देश के करीब 53 करोड़ जनधन खातों, 138 करोड़ आधार कार्ड धारकों और 117 करोड़ मोबाइल उपभोक्ताओं के त्रिआयामी जुड़ाव के जरिये आम आदमी डिजिटल दुनिया से जुड़ गया है। यही नहीं, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की उपलब्धता, जो महज छह करोड़ लोगों तक सीमित थी, पिछले दस वर्षों में करीब 94 करोड़ लोगों तक पहुंच चुकी है। पाठकों को जानकारी देना चाहूंगा कि वैश्विक स्तर पर, भारत बायोमेट्रिक आधारित पहचान (आधार) और वास्तविक समय भुगतान की मात्रा में पहले स्थान पर है। वहीं दूसरी ओर दूरसंचार उपभोक्ताओं में दूसरे स्थान पर है और स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र के मामले में तीसरे स्थान पर है। कुछ समय पहले भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए मुद्रा और वित्त पर जो रिपोर्ट जारी की गई थी, उसके अनुसार भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था वर्तमान में इसके सकल घरेलू उत्पाद(जीडीपी) के दसवें हिस्से का निर्माण करती है जो वर्ष 2026 तक जीडीपी का पांचवां हिस्सा हो जाएगी। कहना ग़लत नहीं होगा कि आज वित्त, खुदरा, निर्यात क्षेत्र में डिजिटलीकरण को लगातार बढ़ावा मिला है। संक्षेप में यह बात कही जा सकती है कि आज भारत डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढाँचे, एक जीवंत वित्तीय प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र और दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती डिजिटल

अर्थव्यवस्था के रूप में उभरने के लिए अनुकूल नीतिगत माहौल का लाभ उठा रहा है। आज भारत में यूपीआइ सिस्टम की प्रशंसा देश-दुनिया में की जा रही है और छोटे से छोटे और बड़े से बड़े भुगतान आनलाइन किए जा रहे हैं। सच तो यह है कि यूपीआई सिस्टम से वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिला है। कितनी अच्छी बात है कि आज गांवों और सूदूर क्षेत्रों में भी आसानी से बैंकिंग सेवाओं का उपयोग हर कोई कर रहा है। आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2023 में रिकॉर्ड तोड़ 118 बिलियन यूपीआई लेनदेन वित्तीय परिदृश्य के डिजिटल परिवर्तन को उजागर करते हैं। कहना ग़लत नहीं होगा कि आज देश में डिजिटल प्रगति ने देश में आय सृजन के नए अवसर पैदा किए हैं। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल भुगतान ने छोटे व्यापारियों व विक्रेताओं को व्यापक बाजार तक पहुंच दी है। माई गर्वनमेंट का उमंग ऐप 50 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ताओं को 1700 से अधिक सरकारी सेवाओं तक आज पहुँच प्रदान कर रहा है। इतना ही नहीं, ई-हॉस्पिटल 380 मिलियन से अधिक पंजीकृत रोगियों के लिए स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच को सरल बनाता है। पीएमजी दिशा ने ग्रामीण समुदायों में 50 मिलियन से अधिक व्यक्तियों को डिजिटल कौशल में प्रशिक्षित और प्रमाणित किया गया है। हालांकि इसी बीच साइबर फ्राड और ठगी एक चिंता का विषय जरूर रहा है। पाठकों को बताता चलूं कि

गृह मंत्रालय ने अपनी 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट में बताया है कि साल 2021 से मार्च 2024 के बीच भारत में 14,570 करोड़ रुपये की साइबर धोखाधड़ी हो चुकी है। इस रिपोर्ट के अनुसार देश में इस दौरान साइबर अपराध की 2.16 करोड़ शिकायतें आ चुकीं हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि शिकायतों की संख्या 2021 में 136,604 से बढ़कर 2022 में 513,334 और 2023 में 1,129,519 हो गई है। 2024 में मार्च तक 381,854 शिकायतें दर्ज की गईं। यह दिखाता है कि देश में जैसे जैसे डिजिटलीकरण को बढ़ावा मिला है, साइबर ठगों के भी हौंसले बुलंद हुए हैं। गौरतलब है कि दुनिया में साइबर हमलों के मामले में अमेरिका के बाद दूसरा नंबर भारत का ही है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि बीते वर्ष यानी 2024 में भारत की 95 इकाइयों को डाटा चोरी का सामना करना पड़ा। यह हैरान कर देने वाली जानकारी साइबर इंटेलिजेंस कंपनी क्लाउडएसइके की ताजा रिपोर्ट में सामने आई है। पाठकों को बताता चलूं कि भारत के गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम एक बार फिर साइबर अपराधियों के पसंदीदा प्लेटफॉर्म बन गए हैं। रिपोर्ट में यह भी खुलासा किया गया है कि साइबर धोखाधड़ी के लिए व्हाट्सएप सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया जाने वाला प्लेटफॉर्म है, लेकिन कहना ग़लत नहीं होगा कि सतर्कता बरतकर इन साइबर ठगी और धोखाधड़ी से बचा जा सकता है। बहरहाल, पीडब्ल्यूसी इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, यूपीआई लेनदेन 2023-24 में 13,100 करोड़ रुपये से तीन गुना बढ़कर 2028-29 में 43,900 करोड़ रुपये हो जाएगा, जो डिजिटल खुदरा लेनदेन का 91 प्रतिशत होगा, जो यह दर्शाता है कि आज देश में यूपीआई समेत विभिन्न डिजिटल सेवाओं में लगातार इजाफा हो रहा है। कहना ग़लत नहीं होगा कि भारत की डिजिटल प्रगति पिछले आठ-दस वर्षों में निस्संदेह सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन का आधार बनी है, जो हाशिए पर खड़े व्यक्ति को भी मुख्यधारा में ला रही है। इससे विश्व स्तर पर भारत की स्थिति काफी मजबूत हुई है। सच तो यह है कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1 जुलाई, 2015 को शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी पहल डिजिटल इंडिया ने पिछले कुछ वर्षों में एक क्रांति का रूप ले लिया है और आज यह एक जन आंदोलन बन गया है। अंत में, यही कहूंगा कि आज आधार, यूपीआई और डिजी लॉकर जैसी पहलों का कार्यान्वयन फेसलेस, कैशलेस और पेपरलेस गवर्नेंस सुनिश्चित कर रहा है जिसने एक मजबूत, सुदृढ़ और सुरक्षित डिजिटल इंडिया की नींव रखी है। निश्चित रूप से आने वाला समय भारत का ही होगा जब हम डिजिटलीकरण की दिशा में नंबर वन बन जायेंगे।

सुनील कुमार महला, फ्रीलांस राइटर, कालमिस्ट व युवा साहित्यकार, उत्तराखंड।

जोमैटो के शेयर हुए धड़ाम, ब्रोकरेज फर्म ने घटाया टारगेट प्राइस; जानें पूरी डिटेल

परिवहन विशेष न्यूज

ब्रोकरेज फर्म जेफरीज का कहना है कि क्विक कॉमर्स सेगमेंट में प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। यहां से Zomato Stock Price जोमैटो के मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा आता है। इस सेगमेंट में जोमैटो के ब्लिंकिट का मुकाबला स्विगी के इंस्टामार्ट जेप्टो और अमेजन जैसी कंपनियों से है। यही वजह है कि जेफरीज ने जोमैटो स्टॉक के लिए टारगेट प्राइस घटा दिया है।

नई दिल्ली। फूड डिलीवरी एग्रीगेटर जोमैटो के शेयर 7 जनवरी को लगभग 5 फीसदी तक गिर गए। यह ट्रेड के दौरान 251.55 रुपये के लो-लेवल तक आ गया था। इसकी वजह ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म जेफरीज की रिपोर्ट है। जेफरीज ने जोमैटो के स्टॉक के लिए रेटिंग और टारगेट प्राइस घटा दिया है।

जोमैटो के शेयरों पर जेफरीज की राय

जेफरीज ने जोमैटो स्टॉक के लिए अपनी रेटिंग को 'Buy' से घटाकर 'Hold' कर दी है। उसने टारगेट प्राइस भी 335 रुपये से कम करके 275 रुपये प्रति शेयर कर दिया है। यही वजह है कि जोमैटो के शेयरों में भारी बिकवाली देखने को मिल रही है।

जेफरीज ने क्यों घटाई जोमैटो की रेटिंग

ब्रोकरेज फर्म का कहना है कि क्विक कॉमर्स सेगमेंट में प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, जहां से जोमैटो के मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा आता है। इस सेगमेंट में जोमैटो के ब्लिंकिट का मुकाबला स्विगी के इंस्टामार्ट, जेप्टो और अमेजन जैसी कंपनियों से है। अगर ब्लिंकिट उनसे मुकाबले के डिस्काउंट बढ़ाती है, तो उसका मुनाफा घट सकता है।

Zomato स्टॉक का प्रदर्शन कैसा रहेगा

जेफरीज का मानना है कि 2025 में जोमैटो के शेयरों कंसॉलिडेशन देखने को मिल सकता है, क्योंकि 2024 के दौरान इसमें दोगुने से अधिक तेजी आई थी। उसका कहना है कि स्टॉक की वैल्यूएशन ज्यादा महंगी नहीं है। बस क्विक कॉमर्स स्पेस में बढ़ती प्रतिस्पर्धा चिंता पैदा कर रही है।

जेफरीज के नोट के अनुसार, इस सेक्टर में नई कंपनियों की एंट्री से सबसे डिस्काउंटिंग की लड़ाई बढ़ सकती है, जो मीडियम टर्म की प्रॉफिटेबिलिटी के लिए खतरा पैदा कर सकती है। उसने जोमैटो के लिए EBITDA और प्रॉफिटेबिलिटी अनुमान में 15 फीसदी से अधिक की कटौती की है।

जोमैटो के शेयरों का क्या हाल है?

जोमैटो के शेयरों ने साल 2024 में काफी शानदार प्रदर्शन किया है। इस दौरान इसने निवेशकों को दोगुने से अधिक रिटर्न दिया। हालांकि, पिछले कुछ समय से इसके शेयरों में गिरावट देखने को मिली है। जोमैटो ने बीते एक महीने में करीब 15 फीसदी का नेगेटिव रिटर्न दिया है। वहीं, पिछले 6 महीने में इससे निवेशकों 22 फीसदी और 1 साल में 90 फीसदी का मुनाफा हुआ है। जोमैटो का मार्केट कैप 2.29 लाख करोड़ रुपये है।

क्या होता है क्रिटिकल इलनेस कवर, किन बीमारियों का मिलता है इलाज?

परिवहन विशेष न्यूज

बीमारियों का इलाज कराना लगातार महंगा होता जा रहा है। खासकर कैंसर या हार्ट जैसी बीमारियों के इलाज में भारी कर्ज होता है। इन्हें सामान्य हेल्थ इंश्योरेंस कवर भी नहीं करता है। इसके लिए आपको क्रिटिकल इलनेस कवर होगा। आइए जानते हैं कि क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस क्या होता है और इसे लेते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए?

नई दिल्ली। कई गंभीर बीमारियां हैं, जिनके इलाज पर काफी रकम खर्च होती है। अगर आपने कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी होगी, तो उसमें सामान्य बीमारियों का इलाज कवर हो जाएगा। लेकिन, कैंसर और हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारियों के वक्त यह काम नहीं आएगा। ऐसे में आपको जरूरत पड़ेगी इलनेस कवर (critical illness insurance) की।

क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस क्या होता है?

कैंसर या हार्ट से जुड़ी बीमारियों के इलाज में काफी रकम खर्च होती है। क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस इन बीमारियों को कवर करता है। इनमें हार्ट अटैक, कैंसर, किडनी फेल, पैरालिसिस, ट्यूमर, कोमा और अंग प्रत्यारोपण जैसे इलाज शामिल हैं। इन सभी बीमारियों का इलाज काफी महंगा होता है। साथ ही, काफी लंबे तक चलता भी है। ऐसे में क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस कवर काफी राहत पहुंचाता है।

क्रिटिकल इलनेस कवर के क्या फायदे हैं?

इसमें आपको उन गंभीर बीमारियों का कवरेज मिल जाता है, जिनके इलाज में लोगों की सारी जमा-पूंजी खत्म हो जाती है। क्रिटिकल इलनेस कवर में 45 साल की उम्र तक किसी मेडिकल चेक-अप की भी जरूरत नहीं होती है। गंभीर बीमारी की स्थिति में कंपनी बीमाधारक को लंपसम (Lumpsum) यानी एकमुश्त भुगतान भी कर सकती है। इसमें सेक्शन 80D के तहत टैक्स छूट भी मिलती है।

इसमें कौन-सी बीमारियां कवर होती हैं?

क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस में हार्ट अटैक, स्ट्रोक, कैंसर, लकवा, अंग प्रत्यारोपण और ब्रेन ट्यूमर जैसी बीमारियां कवर होती हैं। क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से पहले परिवार की मेडिकल हिस्ट्री भी चेक कर लेनी चाहिए। इससे पता लग जाता है कि आपको किन बीमारियों के कवर को ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए।

क्रिटिकल इलनेस कवर की दिक्कतें

क्रिटिकल इंश्योरेंस कवरेज के प्रीमियम काफी ज्यादा होते हैं। खासकर, अगर मरीज पहले से ही किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा हो।

इसमें अूमन सिर्फ गंभीर बीमारियों या चोटों के लिए कवरेज प्रदान करता है, जैसे कि कैंसर, हृदय रोग, या स्ट्रोक।

क्रिटिकल इंश्योरेंस कवरेज के लिए अक्सर लंबा वेटिंग पीरियड होता है, जिस दौरान आप इलाज के लिए क्लेम नहीं कर सकते हैं।

इसकी नियम और शर्तें जटिल हो सकते हैं, जिससे यह समझना मुश्किल हो सकता है कि आपको क्या कवरेज मिलेगा।

क्रिटिकल इंश्योरेंस कवरेज के प्रीमियम समय के साथ बढ़ सकते हैं, जिससे आपको अधिक पैसे खर्च करने

सुस्त पड़ रही भारत की रफ्तार! चार साल के निचले स्तर पर आ सकती है जीडीपी ग्रोथ

परिवहन विशेष न्यूज

भारत की जीडीपी ग्रोथ वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान सुस्त रह सकती है। सरकार के अग्रिम अनुमान में मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान भारत का सकल घरेलू उत्पाद (GDP) 6.4 फीसदी की दर से बढ़ने का अनुमान जताया है। यह चार साल का सबसे निचला स्तर है। पिछले वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था 8.2 फीसदी की दर से बढ़ी थी। आइए जानते हैं कि अर्थव्यवस्था की रफ्तार क्यों पड़ रही है।

नई दिल्ली। भारत की आर्थिक वृद्धि की रफ्तार सुस्त पड़ रही है। सरकार के अग्रिम अनुमान के मुताबिक, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का सकल घरेलू उत्पाद (GDP) 6.4 फीसदी की दर से बढ़ सकता है। यह चार साल का सबसे निचला स्तर है। यह पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले भी ग्रोथ में तेज गिरावट है, जब भारतीय अर्थव्यवस्था 8.2 फीसदी की दर से बढ़ी थी।

किसने जारी किया है जीडीपी ग्रोथ का अनुमान

जीडीपी ग्रोथ का ताजा अनुमान National Statistical Office (NSO) ने जारी किया है। यह वित्त वर्ष 2024-25 के लिए नेशनल इनकम का पहला अग्रिम अनुमान है। इस डेटा के मुताबिक, रीयल ग्रॉस वैल्यू एडेड (GVA) वित्त वर्ष 25 में 6.4 फीसदी की दर से बढ़ने की उम्मीद है। यह वित्त वर्ष 24 में 7.2 फीसदी से कम है। वहीं, नॉमिनल GVA वित्त वर्ष 25 में 9.3 फीसदी की दर से बढ़ने का अनुमान है। यह पिछले वित्त वर्ष में 8.5 फीसदी की ग्रोथ के मुकाबले कुछ अधिक है।

जीडीपी ग्रोथ का अनुमान जारी करने की वजह

एडवांस जीडीपी एस्टिमेट से बजट तैयार करने के लिए अहम डेटा मिलते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2025 को बजट पेश करेंगी। जीडीपी से जुड़े अनुमानों से जो डेटा मिला है, उस हिसाब से उन्हें और उनके मंत्रालय को नीतियां बनने में मदद मिलेगी। जैसे कि कौन-सा सेक्टर सुस्त पड़ रहा है, किसे ज्यादा मदद की जरूरत है आदि। वित्त मंत्री अलग-अलग क्षेत्र के प्रतिनिधियों से मुलाकात भी कर रही हैं, ताकि उनकी समस्याओं को दूर करने वाला बजट पेश कर सकें।

भारत की जीडीपी ग्रोथ धीमी क्यों पड़ रही है?

भारत की अर्थव्यवस्था खपत आधारित है। पिछले कुछ महीनों के दौरान खपत में कमी आई है, जिसका असर इकोनॉमिक ग्रोथ पर देखा जा रहा है।

पिछले कुछ महीने से महंगाई भी काफी ज्यादा बढ़ी है। लेकिन, उस हिसाब से लोगों की कमाई नहीं बढ़ रही है, जिससे चीजों की बिक्री नहीं बढ़ रही।

ऑटोमोबाइल से लेकर कई अन्य सेक्टर की कंपनियों के पास इन्वेट्री भी काफी बढ़ गई है। इसका मतलब है कि मार्केट में डिमांड काफी कम हो गई है।

वैश्विक अनिश्चितता से व्यापार प्रभावित हो रहा है। हूती विद्रोहियों के लाल सागर में हमले ने भारत की आयात-निर्यात पर काफी बुरा प्रभाव डाला है।

भारतीय कंपनियों के तिमाही नतीजे लगातार कमजोर आ रहे हैं। इससे विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से पैसा निकाल रहे हैं। यह भी एक बड़ा फैक्टर है।

भारत में 3 अरब डॉलर का निवेश करेगी माइक्रोसॉफ्ट, 1 करोड़ लोगों को देगी AI ट्रेनिंग

माइक्रोसॉफ्ट का एडवांटेज इंडिया प्रोग्राम अब 2030 तक 2 करोड़ भारतीयों को एआई स्किल में प्रशिक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित कर चुका है। इस पहल के तहत माइक्रोसॉफ्ट ने 24 लाख भारतीयों को ट्रेनिंग दी है। इनमें से 65 प्रतिशत महिलाएं और 74 प्रतिशत लोग छोटे शहरों से थे। यह पहल भारत के युवाओं को एआई के क्षेत्र में रोजगार के लिए तैयार कर रही है।

नई दिल्ली। माइक्रोसॉफ्ट भारत में अपनी क्लाउड कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षमताओं का विस्तार करने के लिए दो साल में तीन अरब डॉलर (लगभग 25,700 करोड़ रुपये) का निवेश करेगी। कंपनी के चेयरमैन और सीईओ सत्य नडेला का कहना है कि अमेरिकी टेक कंपनी 2030 तक भारत में एक करोड़ लोगों को एआई में ट्रेनिंग भी देगी।

नडेला ने कहा कि प्रस्तावित तीन अरब डॉलर का निवेश कंपनी की तरफ से किया जाने वाला अब तक सबसे बड़ा निवेश होगा। नडेला ने अपने भारत दौरे के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की है।

माइक्रोसॉफ्ट का क्या है प्लान

माइक्रोसॉफ्ट अपनी क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज एज्योर के तहत उपलब्ध कराता है। कंपनी के पास 60 से अधिक एज्योर क्षेत्र हैं, जिनमें 300 से अधिक डेटा सेंटर शामिल हैं। नडेला आखिरी बार फरवरी, 2024 में भारत आए थे और तब उन्होंने कहा था कि कंपनी 2025 तक देश में 20 लाख लोगों को एआई स्किल का अवसर प्रदान करेगी। इसका उद्देश्य मुख्य तौर पर छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने पर था।

नडेला ने कहा, 'भारत एआई इनोवेशन में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इससे देशभर में नए अवसर पैदा हो रहे हैं। आज हम बुनियादी ढांचे और कौशल में निवेश का एलान कर रहे हैं, जो भारत को एआई-फर्स्ट बनाने की हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है और यह सुनिश्चित करने में मदद करेगा कि कि देशभर में लोगों और संगठनों को व्यापक रूप से इसका लाभ मिले।'

भारत पर माइक्रोसॉफ्ट का खास फोकस

माइक्रोसॉफ्ट का एडवांटेज इंडिया प्रोग्राम अब 2030 तक 2 करोड़ भारतीयों को एआई स्किल में प्रशिक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित कर चुका है। इस पहल के तहत माइक्रोसॉफ्ट ने 24 लाख भारतीयों को ट्रेनिंग दी है। इनमें से 65 प्रतिशत महिलाएं और 74 प्रतिशत लोग छोटे शहरों से थे। यह पहल भारत के युवाओं को एआई के क्षेत्र में रोजगार के लिए तैयार कर रही है।

माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च लैब्स (MSR) ने एआई इनोवेशन नेटवर्क की शुरुआत की है। इसका मकसद भारत के एआई इकोसिस्टम को रफ्तार देना है। इस नेटवर्क के जरिए रिसर्च के बाद व्यावहारिक और उपयोगी बिजनेस सॉल्यूशंस को डेवलप किया जाएगा। साथ ही, माइक्रोसॉफ्ट और सासबूमी ने मिलकर भारतीय एआई और सास (सॉफ्टवेयर ऐज ए सर्विस) इकोसिस्टम को एक ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा है।

ट्रांसफॉर्मर बनाने के लिए अब नहीं आयात करना होगा स्टील, सरकार ने किया खास इंतजाम

परिवहन विशेष न्यूज

स्टील मंत्री एचडी कुमारास्वामी ने विशेष प्रकार के स्टील के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) स्कीम 1.1 लॉन्च किया। मुख्य रूप से बिजली के ट्रांसफार्मर के साथ ग्रिड इन्फ्रास्ट्रक्चर में इस्तेमाल होने वाले सीआरजीओ स्टील के उत्पादन के लिए अगर कोई कंपनी 3000 करोड़ का भी निवेश करती है तो वह इंसेंटिव का हकदार होगी। पहले यह सीमा 5000 करोड़ थी।

नई दिल्ली। अब बिजली ट्रांसफार्मर व अन्य उद्योगों में इस्तेमाल होने वाले विशेष प्रकार के स्टील के आयात पर हमारी निर्भरता कम हो सकती है। सोमवार को स्टील मंत्री एच.डी. कुमारास्वामी ने विशेष प्रकार के स्टील के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) स्कीम 1.1 लॉन्च किया।

विशेष प्रकार के स्टील उत्पादन के लिए तीन साल पहले भी पीएलआई स्कीम 1.0 की शुरुआत की गई थी, लेकिन कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड (सीआरजीओ) जैसे आठ प्रकार के विशेष स्टील के उत्पादन के लिए इस स्कीम के तहत कोई कंपनी आगे नहीं आई थी। इन स्टील के उत्पादन को घरेलू स्तर पर प्रोत्साहित करने के लिए पीएलआई स्कीम 1.1 के तहत इंसेंटिव पाने की शर्तों में ढील दी गई है।

क्या है इंसेंटिव पाने की शर्त

मुख्य रूप से बिजली के ट्रांसफार्मर के साथ ग्रिड इन्फ्रास्ट्रक्चर में इस्तेमाल होने वाले सीआरजीओ स्टील के उत्पादन के लिए अगर कोई कंपनी 3000 करोड़ का भी निवेश करती है तो वह इंसेंटिव का हकदार होगी। पहले यह सीमा 5000 करोड़ थी। वैसे ही उत्पादन की सीमा को दो लाख टन से घटाकर 50,000 टन कर दिया गया है।

पीएलआई 1.1 के तहत आगामी 31 जनवरी तक इच्छुक कंपनियां आवेदन कर सकेंगी। पहले से पीएलआई स्कीम में शामिल कंपनियां को आवेदन की अनुमति नहीं दी गई है। पीएलआई 1.0 के तहत अब तक 18,300 करोड़ का निवेश हो चुका है जिससे 14,700 रोजगार का सृजन हुआ है।

पीएलआई स्कीम की शर्तों में बदलाव

स्टील सचिव संदीप पोंड्रिक के मुताबिक पीएलआई स्कीम की शर्तों में बदलाव कर पीएलआई स्कीम 1.1 की शुरुआत की गई है। आगामी वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2029-30 तक 1.1 स्कीम के तहत कंपनियां उत्पादन कर सकेंगी। उद्योग जगत के मुताबिक अभी देश में सीआरजीओ स्टील उत्पादन सिर्फ 50,000 टन का है जबकि घरेलू खपत दो लाख टन से अधिक का है। स्टील सचिव के मुताबिक अभी देश में 18 करोड़ टन स्टील बनाने की क्षमता है। हर साल 12-13 प्रतिशत की दर से स्टील की खपत बढ़ रही है। ऐसे में 2030 तक 260-70 लाख टन की मांग घरेलू स्तर पर रहेंगी। इसलिए स्टील के घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए यह स्कीम लाई गई है।

इंडो फार्म ने किया निराश, 19 फीसदी मिला लिस्टिंग गेन; जानें पूरी डिटेल

इंडो फार्म खेती से जुड़ी मशीनें बनाती है। जैसे कि ट्रैक्टर और अन्य हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट। यह पिक एंड कैरी क्रेन भी बनाती है। इसके प्रोडक्ट नेपाल सीरिया सूडान बांग्लादेश म्यांमार जैसे निर्यात भी होता हैं। इंडो फार्म के के प्रमोटर रणबीर सिंह खडवालिया और सुनीता सैनी हैं। इंडो फार्म का बिजनेस साल 2000 में शुरू हुआ। आइए जानते हैं पूरी डिटेल।

नई दिल्ली। इंडो फार्म इक्विपमेंट के शेयरों की शेयर मार्केट में एंट्री फीकी रही। इसने निवेशकों को सिर्फ 19 फीसदी का मुनाफा दिया है। यह आईपीओ 115 रुपये के अपर प्राइस बैंड पर आया था। इंडो फार्म में लिस्टिंग के बाद तेजी दिखी और यह NSE पर दोपहर 12 बजे तक 280 रुपये पर ट्रेड कर रहा था यानी निवेशकों का कुल रिटर्न 30 फीसदी से अधिक हो गया है।

इंडो फार्म इक्विपमेंट का बिजनेस क्या है?

इंडो फार्म खेती से जुड़ी मशीनें बनाती है। जैसे कि ट्रैक्टर और अन्य हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट। यह पिक एंड कैरी क्रेन भी बनाती है। इसके प्रोडक्ट नेपाल, सीरिया, सूडान, बांग्लादेश, म्यांमार जैसे निर्यात भी होता हैं। इंडो फार्म के के प्रमोटर रणबीर सिंह खडवालिया और सुनीता सैनी हैं। इंडो फार्म का बिजनेस साल 2000 में शुरू हुआ। कंपनी IPO से मिलने वाले पैसों का इस्तेमाल कारोबार बढ़ाने और कर्ज चुकाने के लिए करेगी।

इंडो फार्म का वित्तीय प्रदर्शन कैसा है?

इंडो फार्म इक्विपमेंट का रेवेन्यू वित्त वर्ष 23 में 622.84 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 24 में 647.95 करोड़ रुपये हो गया है। इसमें 4.03 फीसदी का उछाल आया है। वहीं, कंपनी का शुद्ध लाभ वित्त वर्ष 23 में 15.37 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 24 में 15.60 करोड़ रुपये हो गया।

वित्त वर्ष 24 में PAT यानी प्रॉफिट ऑफ्टर टैक्स मार्जिन 4.16 फीसदी रहा। इसका डेट-टु-इक्विटी अनुपात 0.01 है। ROE और ROCE क्रमशः 5.13 फीसदी और 8.96 फीसदी हैं। कंपनी अपना कर्ज लगातार घटा रही है। यह वित्त वर्ष 23 में 280.65 करोड़ रुपये से घटाकर वित्त वर्ष 24 में 270.54 करोड़ रुपये कर रहे हैं। इसका मतलब है कि इसमें 3.60 फीसदी की कमी है।

हेमन्त ने 56.61 लाख महिलाओं के खातों में एक हजार 415.44 करोड़ रू किए हस्तांतरित

रांची में मुख्यमंत्री मईया सम्मान योजना का भव्य आयोजन

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड- झारखंड .

रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने रांची के नामकुम स्थित ट्रेनिंग ग्राउंड में महिलाओं का बहु प्रशिक्षित मुख्यमंत्री मंईयाँ सम्मान योजना के राज्य स्तरीय समारोह में 56 लाख 61 हज़ार 791 महिलाओं के बैंक खाते में 1415 करोड़ 44 लाख 77 हज़ार रुपए डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित कर राज्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का उस का चुनावी संकल्प को दोहराया जिसके बदौलत उन्हें गत चुनाव में अपार सफलता मिली। मुख्यमंत्री ने समारोह को संबोधित करते हुए महिलाओं से कहा कि हमने आपसे वादा किया था कि मुख्यमंत्री मंइयाँ सम्मान योजना के तहत हर माह एक हज़ार रुपए की सम्मान राशि को दिसंबर माह से 25 सौ रुपए करेंगे, इसे हम पूरा कर रहे हैं। आज आप सभी के बैंक खाते में बढ़ी हुई राशि की पहली किस्त के रूप में 25 सौ रुपए का हस्तांतरण हो चुका है। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आप सभी अपनी पूरी क्षमता और ताकत के साथ इस राज्य के विकास में अपनी भागीदारी निभाएंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने आधी आबादी को सशक्त बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री मंइयाँ सम्मान योजना की परिकल्पना को जिस मजबूती के साथ धरातल पर उतारा है, उसकी चर्चा पूरे देश मे हो रही है। हमारी इस महत्वाकांक्षी योजना को कई अन्य राज्य रोल मॉडल के रूप में देखते हुए उसे अपनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मैं पूरे यकीन के साथ कर सकता हूं कि महिलाओं को आगे ले जाने में यह योजना निर्णायक साबित होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आपने हमें जो आशीर्वाद और सम्मान दिया है, उससे हमें एक नई ऊर्जा और ताकत मिली है। हमारी सरकार महिलाओं के मान -सम्मान स्वाभिमान और हक अधिकार देने के साथ उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। आपने आगे बढ़ने का जो सपना देखा है, उसे पूरा करने के मकसद से हमने इस योजना को लागू किया है। हमारे इस कदम से आप अपने घर परिवार के साथ राज्य और देश को मजबूती देंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जब तक महिला- पुरुष कदम से कदम मिलाकर नहीं चलेंगे, यह राज्य और देश आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन, अफसोस इस बात का है कि इस देश में कई नीतियां, कार्यक्रम और योजनाएं बनीं, फिर भी आधी आबादी आज भी विकास से कोसों दूर है। महिलाओं को वह ताकत नहीं मिला, जिसके माध्यम से वे खुद और अपने घर परिवार के साथ राज्य और देश के विकास का हिस्सा बन सके। इसी बात को ध्यान में रखकर हमने महिलाओं को आगे बढ़ने का संकल्प लिया। इस दिशा में मुख्यमंत्री मंइयाँ सम्मान योजना के माध्यम से कदम बढ़ाने का काम किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री मंइयाँ सम्मान योजना के माध्यम से हमारी सरकार ने एक ऐसी व्यवस्था आपको दी है , जिसमें आपके सपनों को पूरा करने की पूरी क्षमता होगी। आप इस पैसे से ना सिर्फ अपनी जरूर को पूरा कर सकेंगे बल्कि उसके माध्यम से अपने बच्चों के बेहतर पठन-पाठन के साथ अपनी आमदनी को बढ़ाने का भी मौका मिलेगा। यह सिर्फ एक योजना मात्र नहीं है बल्कि आपको आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने का एक सशक्त माध्यम है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाएं घर परिवार भी चलाती हैं और कामकाज भी करती है। ऐसे में पैसे का महत्व उनसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। यही वजह है कि हमारी सरकार घर- परिवार चलाने वाली महिलाओं पर राज्य को आगे ले जाने का जिम्मा भी सौंप रही है। अब महिलाओं के जरिए राज्य की अर्थव्यवस्था का पहिया घुमाने का प्रयास हो रहा है, क्योंकि इस राज्य को विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा करने में आधी आबादी की अहम भूमिका होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस राज्य की बहन -बेटियों को सशक्त बनाने के लिए सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। हमारी सरकार समय-समय पर गांव- और देहातों का भ्रमण भी करेगी और यह जानने की कोशिश करेगी कि आर्थिक समृद्धि के लिए आपके द्वारा किन-किन गतिविधियों को संचालित किया जा रहा है। इस दिशा में सरकार के द्वारा आपको आगे भी पूरा सहयोग मिलेगा

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस राज्य के संसाधनों के जरिए दूसरे राज्य रोशन हो रहे हैं। लेकिन, वर्षों से यहां के लोग अभाव की जिंदगी जीने को मजबूर हैं। पिछड़ापन, गरीबी, बेरोजगारी, शोषण कुपोषण और पलायन जैसी समस्याएं आज भी इस राज्य के विकास में सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। यहां के नीति - निर्धारकों की नजर में यह राज्य हमेशा हाशिये पर रहता आया है। लेकिन, अब ऐसा नहीं चलेगा। इस राज्य को पिछड़ापन और गरीबी से मुक्ति दिलाएंगे और अग्रणी राज्यों की श्रेणी में खड़ा करेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड के प्रति बैंकों का रुख बहुत अच्छा नहीं है। यहां के गरीब लोग बैंकों में जो पैसा जमा करते हैं, उसका इस्तेमाल कहीं और होता है। यहां के लोगों को बैंकों से जो मदद मिलनी चाहिए वह नहीं मिलती है, लेकिन अब बैंकों को अपना रुख बदलना होगा और इस राज्य और यहां के लोगों की जरूरत के अनुरूप उन्हें कार्य करना होगा।

इस समारोह में मंत्री राधा कृष्ण किशोर, मंत्री चमरा लिंडा, मंत्री संजय प्रसाद यादव, मंत्री इरफान अंसारी, मंत्री हफीजुल हसन, मंत्री दीपिका पांडेय सिंह, मंत्री योगेंद्र प्रसाद, मंत्री श्री सुदिव्य कुमार, मंत्री श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की, सांसद श्रीमती जोबा मांझी, राज्यसभा सांसद श्रीमती महुआ माजी, सभी विधायकगण, अन्य गणमान्य अतिथिगण, राज्य सरकार के वरीय अधिकारीगण एवं सभी जिलों से बड़ी संख्या में पहुंचे मंईयां सम्मान योजना के लाभुक महिलाएं उपस्थित रहे।

एयरपोर्ट से 10 करोड़ रुपये का मारिजुआना जब्त: मलेशिया से ओडिशा के रास्ते कोलकाता जा रहा था

मनोरंजन सासमल , स्टेट हेड ओड़िशा

भुबनेश्वर: सीमा शुल्क विभाग ने भुवनेश्वर बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बड़े पैमाने पर मादक पदार्थों की तस्करी का भंडाफोड़ किया है। पश्चिम बंगाल की दो महिलाओं को मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर से खतरनाक ड्रग मारिजुआना लाते समय भुवनेश्वर हवाई अड्डे पर पकड़ा गया। उनके पास से 9 किलो 524 ग्राम मारिजुआना जब्त किया गया।सीमा शुल्क विभाग ने इस माल की कीमत लगभग 10 करोड़ रुपये आंकी है। दोनों को एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के तहत गिरफ्तार किया गया और जमानत देने से इनकार करने के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। यह पुष्टि की गई है कि दोनों को आगे की पूछताछ के लिए सीमा शुल्क विभाग द्वारा रिमांड पर लिया जाएगा।सीमा शुल्क अधिकारियों को खुफिया रिपोर्ट मिलने के बाद सतर्क कर दिया गया कि कुआलालंपुर-ओडिशा मार्ग पर उड़ान भरने वाले एक विमान में मादक पदार्थों की तस्करी की जा रही है। यात्रियों के सामान की जांच करते समय कस्टम अधिकारी को दोनों महिलाओं की स्थिति पर संदेह हुआ। दोनों के बैग की तलाशी के दौरान 19 पैकेटों में ये सभी खतरनाक ड्रग्स बरामद हुए। जब्त सामान की जांच के बाद पता चला कि वह मारिजुआना है। इस बात की जांच शुरू कर दी गई है कि पकड़ी गई दोनों महिलाओं ने ड्रग्स कहां से एकत्र की थी और वे उन्हें कहां ले जा रही थीं। दूसरी ओर, इस बात की भी जांच की जा रही है कि इनका किसी बड़े ड्रग माफिया गिरोह से संबंध तो नहीं है। इतनी बड़ी मात्रा में मादक पदार्थों की जब्ती चर्चा का विषय बन गई है, क्योंकि एक दिन बाद ही राजधानी में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जा रहा है।

वर्चुअल टोकन... माता-पिता का वेरिफिकेशन, तब खुलेगा सोशल मीडिया अकाउंट; क्या है मोदी सरकार का नया नियम?

मोदी सरकार के नए डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (डीपीडीपी) नियम के तहत अब नाबालिगों के लिए सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट खोलना आसान नहीं होगा। अकाउंट खोलने से पहले माता–पिता की सहमति लगेगी। वर्चुअल टोकन के माध्यम से माता––पिता का सत्यापन किया जाएगा। अगर उम्र 18 साल से अधिक है तो सत्यापन की जरूरत नहीं होगी। जानिए क्या है यह नियम?

नई दिल्ली। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (डीपीडीपी) नियम के तहत सोशल मीडिया पर अकाउंट खोलने के दौरान वर्चुअल टोकन के जरिए बच्चे व उनके माता-पिता का सत्यापन किया जाएगा।

डेटा संरक्षण के प्रस्तावित नियम के तहत 18 साल से कम आयु का बच्चा अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अकाउंट खोलने जाता है तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को उसके माता-पिता की सहमति लेनी होगी। सही में वे उसके माता-पिता है या नहीं और उनकी सहमति का सत्यापन वर्चुअल टोकन के जरिए होगा।

अस्थायी होगा वर्चुअल टोकन

इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी मंत्रालय के मुताबिक वर्चुअल टोकन सत्यापन के वक्त जेनरेट होगा और अस्थायी होगा। डिजिटल डाटा का उपयोग करके वर्चुअल टोकन जेनरेट किया जाएगा। हालांकि आईटी सेक्टर के जानकार इस बात को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि मसौदे के मुताबिक सोशल मीडिया पर अकाउंट खोलने के दौरान माता-पिता की सहमति या उनके सत्यापन की जरूरत तब होगी जब बच्चा अपनी उम्र 18 साल के कम बताता है।

टोकन सिस्टम पर उठे सवाल

अकाउंट खोलने के दौरान अगर कोई बच्चा खुद को 18 साल से अधिक उम्र का बताता है तो किसी सहमति की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे में सवाल यह उठने लगा है कि कोई बच्चा खुद को 18 साल से कम उम्र का क्यों बताएगा?

एक्सपर्ट से समझें पूरा मामला

आईटी विशेषज्ञ सुप्रीम कोर्ट के वकील पवन दुग्गल कहते हैं कि नियम का यह मसौदा पर्याप्त नहीं है। क्योंकि कोई भी बच्चा यह जानने के बाद कि 18 साल से कम उम्र बताने पर उसे अकाउंट खोलने के लिए माता-पिता की सहमति लेनी होगी, वह खुद को 18 साल या इससे अधिक उम्र का ही बताएगा।

प्लेटफॉर्म पर लग सकता 250 करोड़ का जुर्माना

दुग्गल कहते हैं कि दूसरी तरफ 18 साल से कम उम्र के बच्चे का अकाउंट खुल जाने पर कोई माता-पिता सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की इस बात को लेकर शिकायत कर सकता है कि उसके बच्चे का अकाउंट कैसे खुल गया और इस बात के लिए उस प्लेटफार्म पर 250 करोड़ तक का जुर्माना हो सकता है। उनका कहना है कि इस नियम को और समग्र रूप में लाने की जरूरत है।

सरकार ने पूरे मामले में क्या कहा?

मंत्रालय का कहना है कि हमारे देश की डिजिटल व्यवस्था बहुत ही अच्छी है और डिजिटल डाटा का उपयोग करके यह पता लग जाएगा कि किसी बच्चे की उम्र क्या है? मंत्रालय के मुताबिक डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण नियम में कंसेंट मैनेजर की भूमिका अहम होगी। कंसेंट मैनेजर कोई व्यक्ति या कोई संस्था भी हो सकती है जो डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया के तहत पंजीकृत होगा। कंसेंट मैनेजर की जिम्मेदारी होगी कि उपभोक्ता का डाटा उचित जगह पर पहुंचे।

प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या राममंदिर प्राण प्रतिष्ठा की प्रथम वर्षी में विश्व का पहला पंच केदार मंदिर और विशाल नंदीशाला का शिलान्यास करेंगे

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी द्वारा अयोध्या राममंदिर प्राण प्रतिष्ठा की प्रथम वर्षी 22 जनवरी को हैदराबाद, यलमपेट, मेडचल में विश्व का पहला पंच केदार मंदिर और विशाल नंदीशाला का शिलान्यास करेंगे तेलंगाना के महामहिम राज्यपाल श्री जिष्णु देव वर्मा जी और लेडी राज्यपाल महोदया श्रीमती सुधा वर्मा जी।

आज प्रेस विज्ञप्ति में श्री दक्षिणेश्वर केदारनाथ मंदिर ट्रस्ट के चेयरमैन राजर्षी जयपाल नयाल सनातनी ने बताया कि देश के वरिष्ठ संत धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी के विचारों के प्रखर वक्ता स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी के पावन सानिध्य में तेलंगाना के महामहिम राज्यपाल महोदय श्री जिष्णु देव वर्मा और लेडी राज्यपाल महोदया के करकमलों से आगामी 22 जनवरी बुधवार के दिन प्रातः 8.34 से 9.45 पर कुम्भ लग्न में उत्तराखंड के विद्वान ब्राह्मणों के मार्गदर्शन में शिलान्यास का भव्य कार्यक्रम सुनिश्चित है।

रविवार 5 जनवरी को हैदराबाद राजभवन में श्री दक्षिणेश्वर केदारनाथ मंदिर ट्रस्ट के विद्वान ब्राह्मणों द्वारा तैयार किया 2025 नववर्ष के हिंदी कलेंडर का लोकार्पण करते हुए महामहिम राज्यपाल महोदय ने सभी उत्तराखंड वासियों को बधाई दी और राज्यपाल महोदया के साथ शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने की स्वीकृति प्रदान की।

आज 7 जनवरी पूज्य अभिषेक ब्रह्मचारी जी महाराज और युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने ताज कृष्णा होटल बंजारा हिल में तथा IPS अभिलाषा बिष्ट ने पुलिस एकेडमी (डायरेक्टर) में केदारनाथ मंदिर ट्रस्ट के कलेंडर को लोकार्पित किया।

स्वागत समिति के अध्यक्ष राम भाटी ने बताया कि विशिष्ट अतिथि के रूप में देश की राजधानी दिल्ली से युवा चेतना मंच के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह, भाजपा ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लक्ष्मण , सांसद इटेला राजेंद्र, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मैनमपल्ली हनुमंत राव, कुलम हनुमंत रेड्डी, तथा शैलम गौड आदि अनेक प्रमुख राजनेता और उद्योगपति आमंत्रित है।।

इस अवसर पर देवभूमि उत्तराखंड सेवा संस्थान की महिला अध्यक्षा दीप्ति रावत ने उत्तराखंड और समस्त भाग्यनगर की माताओं - बहनों से श्री दक्षिणेश्वर केदारनाथ मंदिर और नंदीशाला के शिलान्यास कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने की प्रार्थना की।

18वें प्रवासी भारतीय दिवस 2025 केलिए भुबनेश्वर सड़कें सुबह 8 से 10 बजे तक बंद रहेंगी

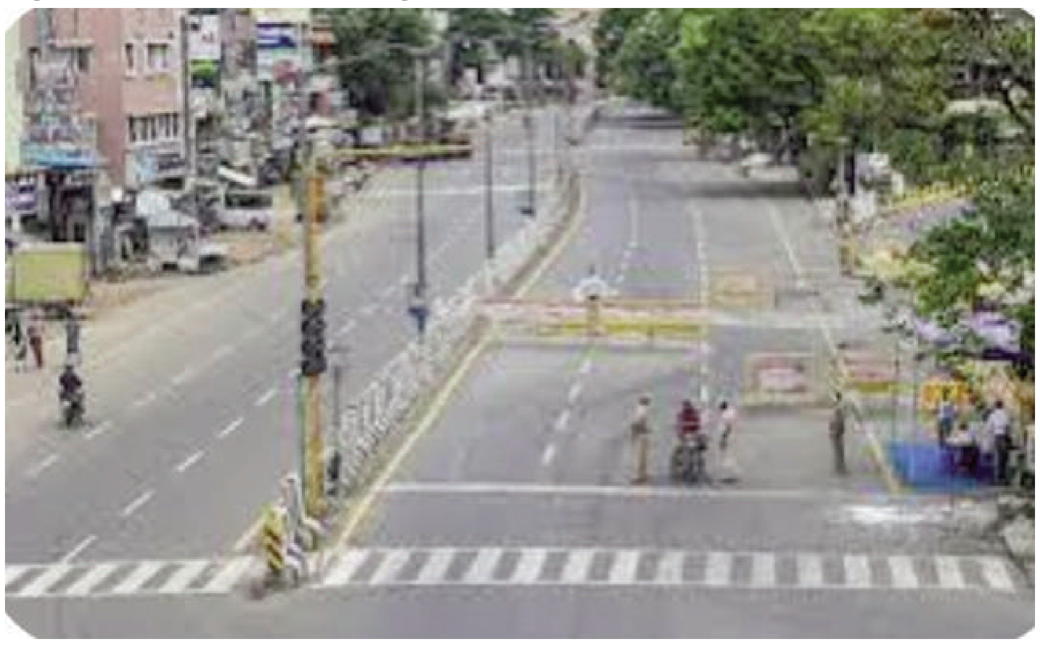

मनोरंजन सासमल , स्टेट हेड ओड़िशा

भुबनेश्वर: भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री राजधानी भुवनेश्वर में आयोजित होने वाले 18वें प्रवासी भारतीय दिवस 2025 में भाग लेने के लिए 8 से 10 जनवरी तक ओडिशा के दौरे पर आ रहे हैं। वीआईपी और वीवीआईपी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कमिश्नरेट पुलिस ने कुछ प्रतिबंध लगाए हैं। इस प्रतिबंध के अनुसार, इस सड़क पर कोई भी वाहन नहीं चल सकता।बुधवार (8 जनवरी) को एयरपोर्ट चौक-अस्पताल चौक-एजी चौक-राजभवन मार्ग शाम 7.50 बजे से 8.20 बजे तक बंद रहेगा।

गुरुवार (9 जनवरी) को राजभवन चौक-शास्त्रीनगर चौक-जयदेव बिहार-जेवियर चौक मार्ग सुबह 9:30 बजे से 10 बजे तक बंद रहेगा।

एयरपोर्ट चौक-एजी चौक-राजभवन मार्ग शाम 4:20 बजे से 4:50 बजे तक बंद रहेगा।

शुक्रवार (10 जनवरी) को राजभवन चौक-शास्त्री नगर चौक-जयदेव बिहार चौक-नालको चौक मार्ग सुबह 11:20 बजे से 11:50 बजे तक बंद रहेगा। इसी तरह शाम 4:50 बजे से 5:25 बजे तक नाल्को चौक-जेवियर चौक-जयदेव विहार चौक-शास्त्री नगर चौक-राजभवन चौक-एजी चौक-अस्पताल चौक-एयरपोर्ट चौक मार्ग बंद रहेगा।

सेरोगेसी के लिए कितनी होनी चाहिए उम्र? 11 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला

सेरोगेसी कानून में मां और अन्य के लिए तय उम्र सीमा पर विचार करने के लिए राजी हो गया है। इस मामले में शीर्ष न्यायालय 11 फरवरी को विचार करेगा। इस कानून से जुड़ीं एक दर्जन से अधिक याचिकाएं कोर्ट में लंबित हैं जिनमें उम्र सीमा से संबंधित प्रविधानों को चुनौती दी गई है। शीर्ष न्यायालय ने केंद्र सरकार से कहा कि वह मामले में लिखित दलीलें दाखिल करे।

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट सेरोगेसी कानून में मां और अन्य के लिए तय उम्र सीमा के मुद्दे पर विचार को राजी हो गया है। इस मामले में शीर्ष कोर्ट 11 फरवरी को विचार करेगा। सुप्रीम कोर्ट में एक दर्जन से ज्यादा याचिकाएं लंबित हैं जिनमें उम्र सीमा से संबंधित प्रविधानों व अन्य उपबंधों को चुनौती दी गई है।

दरअसल, 2021 में लाए गए सरोगेसी कानून में इसके जरिए माता पिता बनने की चाहत रखने वालों और सेरोगेट मां के लिए उम्र सीमा तय है। कानून के मुताबिक मां बनने की चाहत रखने वाली महिला की उम्र 23 से 50 वर्ष और पिता बनने की चाहत रखने वाले पुरुष की आयु 26 से 55 वर्ष की होनी चाहिए।

इसके अलावा सेरोगेट मां विवाहित होनी चाहिए और उसकी आयु 25 से 35 वर्ष होनी चाहिए। उसका अपना एक बच्चा भी होना चाहिए और वह जीवन में एक ही बार सेरोगेट मां बन सकती है। कानून में सेरोगेसी को नियंत्रित और नियमित करने की शर्तें भी हैं।

केंद्र से मांगी लिखित दलीलें

मंगलवार को सेरोगेसी कानून से संबंधित याचिकाएं न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और सतीष चंद्र शर्मा की पीठ के समक्ष सुनवाई पर लगीं थीं। पीठ ने केंद्र सरकार से कहा कि वह मामले में लिखित दलीलें दाखिल करें। केंद्र सरकार की ओर से पेश एडीशनल सालिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि केंद्र लिखित दलीलें दाखिल करेगा और कोर्ट के निर्देशों का पालन करेगा।

पीठ ने सुनवाई के दौरान मामले में अंतरिम आदेश की जरूरत पर भी बल दिया। कोर्ट ने सेरोगेट मां के हित संरक्षित करने पर जोर देते हुए कहा कि शोषण रोकने के लिए एक मजबूत तंत्र होना चाहिए। खास कर यह ध्यान रखते हुए कि भारत में व्यवसायिक सेरोगेसी पर रोक है।

सेरोगेट महिलाओं का डाटाबेस किया जाए तैयार

कोर्ट ने कहा कि एक डेटाबेस हो सकता है ताकि एक ही महिला का शोषण न हो। एक सिस्टम होना चाहिए। कोई यह नहीं कह रहा कि यह विचार बुरा है लेकिन इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। पीठ ने सेरोगेट मां को मुआवजे के बारे में एक वैकल्पिक तंत्र विकसित किए जाने पर भी चर्चा की।

बता दें कि कोर्ट का सुझाव था कि माता-पिता बनने की चाहत रखने वाले सेरोगेट मां को पैसे बांटे इसके बजाए एक डिजिग्नेटेड अथारिटी होनी चाहिए। सीधे सेरोगेट मां को पैसे देने की जरूरत नहीं है वह रकम जमा करा दें और विभाग रकम दे। ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि कानून सिर्फ परोपकार के लिए सेरोगेसी की इजाजत देता है कानून में व्यवसायिक उपयोग के लिए सैरोगेसी की मनाही है।

भाटी ने आगे कहा कि सरकार कोर्ट के सुझावों पर विचार करेगी। याचिकाकर्ता का कहना था कि परोपकार के लिए सेरोगेसी अच्छी बात है लेकिन कानून में सेरोगेट माताओं के लिए पर्याप्त मुआवजा तंत्र की कमी ने चुनौतियां पेश की हैं। मौजूदा प्रविधान सिर्फ चिकित्सा खर्च और बीमा को कवर करते हैं जो कि अपर्याप्त हैं। इस मामले में चेन्नई के डाक्टर अरुण मुथवेल मुख्य याचिकाकर्ता हैं।

सड़कों से गालों का रिश्ता... !

तय किया लालू ने किस्सा,
सड़कों से गालों का रिश्ता।
वो एक ही थी मालिनी,
सड़क ना हुई शालिनी।
नीतिश तो भए कृपालिनी,
सत्ता हो गई स्थानांतरिणी।

तय किया लालू ने किस्सा,
सड़कों से गालों का रिश्ता।
बिधूड़ी कौनसे है फरिश्ता,
प्रियंका के गालों की निष्ठा।
रमेश बदल रहे है रिश्ता,
आतिशी मन आँसू में भिगता।

तय किया लालू ने किस्सा,
सड़कों से गालों का रिश्ता।
बिधूड़ी सालों बाद दे जवाब,
विपक्षी तो हो गए है नवाब।
सब पडे.है पीछे मांगों माफी,
हो गया प्रचार यहीं था बाकी।

संजय एम. तराणेकर

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी–18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए–4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली– 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023